

1.00 P.M.

किसी को 300 रुपये, किसी को 900 रुपये, किसी को 1500 रुपये और किसी को 2000 रुपये मिल रहे थे। कच्छ एरिया में अर्थ-क्वेक आया लेकिन उसके साथ-साथ सौराष्ट्र के कुछ जिले हैं, नार्थ गुजरात के भी कुछ जिले हैं जो कि उससे अफेक्टिड हैं। वहां भी उतना ही नुकसान हुआ है जितना

श्री सभापति : मिस्टर अहमद एक बज गया है आप लंच के बाद कंटीन्यु करें। The House is adjourned for lunch till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after Lunch at two minutes past two of the clock,
THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us have the Railway Budget first.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2001-2002

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE):
Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2001-2002 in respect of Railways. [Placed in Library. See No. LT. 3266/01]

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): मैडम, यह बजट तो पूरा बंगाल का बजट है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): आपको तो खुश होना चाहिए, कम्यूनिस्टों को खुशी होनी चाहिए।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार): मैडम, आगामी चुनाव को देखकर बजट बनाया गया है, अपने फायदे को देखते हुए बनाया गया है।

उपसभापति : जब डिस्कशन होगी तो उसके अंतर्गत आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी कमेंट करने से क्या फायदा? अब तो जो आना था, आ ही गया है।

श्री बालकवि बैरागी : मध्य प्रदेश के मामले में ममता जी बड़ी निर्मम साबित हुई हैं, उनमें सारी ममता नष्ट हो गयी है।

उपसभापति : महाराष्ट्र के बारे में क्या हुआ, वह मुझे नहीं पता है। वह देखना है। अहमद पटेल जी, आप बोल रहे थे।

**STATEMENT AND DISCUSSION ON THE SITUATION CAUSED BY
SEVERE EARTHQUAKE ON 26TH JANUARY, 2001 IN GUJARAT - Contd.**

श्री अहमद पटेल : महोदया, मैं गुजरात में भूकम्प की वजह से जो नुकसान हुआ, जो हादसा हुआ, उसके रेस्क्यू, रिलीफ और रीहैबिलिटेशन के बारे में जिक्र कर रहा था। वह बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा काम था, मुश्किल काम था लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर ठीक तरह से को ऑर्डिनेशन होता, आयोजन होता या कुछ इच्छा शक्ति होती तो मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू में बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं। रिलीफ का काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता था। क्योंकि वहाँ गांव के गांव खत्म हो गये, भुज के सरकारी अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो गए और स्टाफ के साथ चार सौ लोग मारे गये। भुज का जो कलेक्टर का ऑफिस था, वह पूरी तरह खत्म हो गया। जिला परिषद का आफिस खत्म हो गया और यहां तक कि जो जेल में कैदी थे, वे भी भाग गए। पता नहीं उसमें से कितने पकड़ पाए और कितने नहीं पकड़ पाए। जब हमने उनसे डिसकशन किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक दो कैदियों को नहीं पकड़ पाए हैं बाकी के कैदियों को पकड़ लिया है। सामा ख्यानी का शमशान दाह दस फीट अंदर धंस गया है और भचाऊ पूरी तरह तबाह हो गया है। अंजार और गांधीधाम में भी काफी नुकसान हुआ है। उद्योग और व्यवसाय खत्म हो गए हैं। भूकम्प की वजह से जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान खोफ की वजह से हुआ है क्योंकि डर के मारे लोग न तो वहां दुकानें खोल रहे हैं और न ही अपना कारोबार व रोजगार चला रहे हैं। इसी तरह से हस्तकला और गृह उद्योग में खासतौर पर जिन लोगों को एम्बाइडरी, छापे के काम व वीविंग में नेशनल एवार्ड मिले थे उन सभी के परिवारों को काफी नुकसान पहुंचा है और उनका रोजगार बन्द हो गया है। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। खासतौर पर भुज, मोरबी और दांगदा में जो हमारे मान्युमेंट्स थे और बाकी जगह जो प्रोटेक्टिव मान्युमेंट्स थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। मेरे ख्याल से यह काम बहुत मुश्किल था। अगर सरकार ठीक तरह से को आर्डिनेट कर लेती तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी और रिलीफ वर्क अच्छी तरह से हो सकता था। मुझे नहीं मालूम कि रीहैबिलिटेशन में क्या होगा? कच्छ ड्राउट प्रोन एरिया भी है और सूखे की वजह से मेरे ख्याल से पिछले तीन वर्षों से, 1998 से साइक्लोन भी आया है, जिसकी वजह से 1500 लोग मारे गए हैं और 1700 लोग अभी भी गायब हैं। तब भी 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था और पांच हजार मवेशी मारे गए थे। जिन लोगों का साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ था उनकी प्रोब्लम्स अभी तक पेंडिंग हैं। वहां से काफी डेलीगेशन्स हमसे मिले, कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिले और अन्य लोगों से भी मिले लेकिन अभी तक भी उनकी प्रोब्लम्स हल नहीं हो पाई हैं। उनको अभी तक भी कम्पन्सेशन नहीं मिला है। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से तब भी 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और आज जो नुकसान हुआ है, सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं उस हिसाब से बीस हजार करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। यह एक बहुत बड़ा काम है। मैं रेस्क्यू, रिलीफ के लिए अपनी सेना, अर्धसैनिक बलों, पैरा मिलिट्री फोर्स को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ ही मैं अपने एनजीओज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे वालेंटियर्स चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें लोगों की तरफ से कुछ ऐसी शिकायतें और रिप्रेजेंटेशन्स भी मिले हैं कि कुछ डिसक्रिमिनेशन किया जा रहा है। हम कंसर्नर्ड अथॉरिटी के ध्यान में ये चीजें लाएं, कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहां भी हमें ध्यान देना होगा। यह प्राकृतिक आपदा कोई मानव सृजित आपदा

नहीं है, सरकार सृजित आपदा नहीं है, यह एक मुश्किल काम है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मृत्यु के आंकड़े सही क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, क्या सरकार भुआवजा देने से डरती है? जब पहले दिन हम लोग अहमदाबाद में मुख्य मंत्री से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया था कि काफी लोगों की मृत्यु हुई इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। फिर लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और लोगों को पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट नहीं मिला। यह सरकार का निर्णय था। अब जब कम्पनसेशन की बात आई तो पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? कम से कम सही फिगर्स तो आनी चाहिए और जिनके परिवारों की डेथ हुई है उनको पैसा मिल, यह बहुत ही जरूरी है। अभी मकान का कम्पनसेशन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि सर्वे बहुत लेट शुरू हुआ है। यहां पर जो फिगर्स दी हैं मंत्री जी ने, गुजरात सरकार ने, पक्के मकान, कच्चे मकान और हट्स की, क्योंकि रि-हेबिलिटेशन का काम शुरू हो इससे पहले मैं रिलीफ की बात करना चाहूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कैश डोल या पीडीएस से जो डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए, यह बहुत लेट शुरू हुआ है। यह बारह, तेरह या चौदह दिन के बाद शुरू हुआ है। पीडीएस से जो मैटीरियल डिस्ट्रिब्यूट हो रहा था उसके लिए राशन कार्ड मांगा जा रहा था। अब जिनके मकान दह गए, मलबे में जिनके राशन कार्ड दब गए उनसे राशन कार्ड क्यों मागे जा रहे थे। बाद में यह सुधारा गया। मेरे ख्याल से जिस गांव का मुखिया जिंदा है वह या कमेटी यह सर्टिफाई करे तो उनको मैटीरियल देना चाहिए। इसके बावजूद राशन कार्ड मांगा जा रहा था। कैश डोल में कच्चे के लिए कुछ है और सौराष्ट्र के लिए कुछ है। मैं समझता हूँ कि सौराष्ट्र का भी उतना ही नुकसान हुआ है और वहां भी गांव के गांव खत्म हो गए हैं, नार्थ गुजरात में भी खत्म हो गए हैं। मैं मंत्री जी से डिमांड करूंगा कि यह पैकेज कच्चे और सौराष्ट्र दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अभी मुख्य मंत्री ने डिमांड की है कुछ एक्जेंप्शन के बारे में, एक्साइज, और इन्कम टैक्स के बारे में। सिर्फ कच्चे के लिए डिमांड क्यों आई है, सौराष्ट्र के बाकी जिलों के लिए और नार्थ गुजरात के लिए क्यों नहीं आई है? मैं समझता हूँ कि यह भी होना चाहिए। खास तौर पर अभी भी जो रिलीफ मैटीरियल बांटा जा रहा है उसमें डिस्ट्रिब्यूशन न हो या लोगों को तकलीफों का सामना न करना पड़े, राशन कार्ड न मांगा जाए और यह सही लोगों को सही वक्त पर पहुंचे, यह बहुत जरूरी है। लोगों को सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह छत है। उन्हें रहने के लिए छत चाहिए, टेंट चाहिए, लंबू चाहिए। शुरू में टेंट की मांग कर रहे थे अभी कह रहे हैं कि उन्हें टैम्पररी शैल्टर्स चाहिए। क्योंकि वे जानते हैं कि यहां जो फिगर दी गई है तकरीबन 3,44,000 टोटल पक्के, कच्चे और हट्स मिलाकर डिस्ट्राय हो गए हैं और आपने जो आंकड़े दिए हैं उस हिसाब से भी 3,44,000 टेंट चाहिए। अभी तक जो टेंट बांटे गए हैं वे हार्डली 10 परसेंट यानी 40,45 हजार टेंट बांटे गए हैं एक महीने के बाद। एक महीना हो गया है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये टेंट कहाँ से आएंगे? कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम तो होना चाहिए कि कब तक ये टैम्पररी शैल्टर्स या टेंट्स आठ लोगों को प्रोवाइड करेंगे? बाकी चीजे जैसे मकान आदि बनाने का सवाल तो बाद में आएगा। यह कैसे होगा? कम से कम 6 लाख और 80 हजार मकान डैमेज हुए हैं। 3 से 4 लाख पक्के मकान डैमेज हुए हैं, करीबन 3,00,000 कच्चे मकान डैमेज हुए हैं, 31,000 हट्स डैमेज हुई हैं। इनमें से 50 परसेंट तो रिपेयर के लायक भी नहीं हैं। क्योंकि अगर बड़ी ब्रेक है तो वह रहने के लिए, जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वह ग़ाहिर बंटा हुआ है। उस दर है कि वह खत्म हो जाएगा। उसे रिपेयर करने वाला रिपेयर कर ही नहीं सकता। इसलिए ये मकान भी बनाने पड़ेंगे। तकरीबन आठ लाख हट्स, कच्चे

मकान, पक्के मकान बनाने पड़ेगे। मेरा खयाल है कि 6 या 7,000 मकान हर रोज बनाएंगे तब जाकर काम होगा। मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया था, बयान दिया था कि मानसून से पहले तक हर एक व्यक्ति के पास छत होगी, घर होगा। पता नहीं कहां से करेंगे, क्या करेंगे? उनके पास क्या प्लानिंग है? क्या योजना है? अगर एक मकान बनाना है तो कम से कम एक मेसन चाहिए, एक कारपेंटर चाहिए। इतने सारे मेसन्स, इतने सारे कारपेंटर्स और इतने सारे इलेक्ट्रिशियन्स, इतने सारे प्लम्बर्स कहा से आएंगे? बाकी लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। मैं समझता हूं इसके साथ ही लोगों को रोजगार मिले इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। वहां के लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। उन्हें प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाए, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाए, कारपेंटर की ट्रेनिंग दी जाए जिससे कम से कम उन्हें रोजगार तो मिले। क्योंकि सारे लोग तो मजदूरी नहीं कर पाएंगे तो जो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जैसे कारपेंटर का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसाकि आपने कहा है कि सरकार वार फुटिंग पर काम कर रही है तो यह टेंट कब तक मिल जाएंगे, बाकी आप कब तक उपलब्ध कराएंगे? आपके पास है या नहीं? टेम्परेरी शैल्टर्स की अधिक मांग कर रहे हैं क्योंकि कुछ टेंट्स तो ऐसे हैं जो बारिश में टिक ही नहीं पाएंगे। वे फिर से सड़क पर आ जाएंगे। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्या प्रावधान करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों पर ध्यान देना बहुत मुश्किल काम है। खास कर प्रदेश सरकार को इसके लिए ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। जब प्राकृतिक आपदा आई तो शुरू में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हम ब्लैक बैंक दे देंगे पर पता नहीं उस ब्लैक बैंक का क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए कुछ मिनिस्टर्स को साथ लेकर, वहां उन्होंने एनाउंस किया कि हम पांच सौ करोड़ रुपये एडहोक दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन से स्तर पर पांच सौ करोड़ रुपये दिए गए। सॉफ्ट लोन है, ग्रांट है या वॉरिस करने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा है? जब बीस, इक्कीस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और पांच सौ करोड़ रुपये दे रहे हैं और वहां की सरकार ने अभी इमिजिएटली 7-8,000 करोड़ मांगे हुए हैं तो सरकार कब तक उस राशि उनकी सरकार को उपलब्ध कराएगी? कौन से स्तर पर देगी? सॉफ्ट लोन होगा, क्या होगा, यह चिन्ता का विषय है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा काम कैसे हो जाएगा? वहां की सरकार को मदद देने की जरूरत है। पिछले दो साल में कम से कम तीस हजार करोड़ रुपये वहां के गुजरात के लोगों से चाहे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, करटम ड्यूटी पर यह रिवेन्यू वहां से हुआ है। अब जब वहां पर प्राकृतिक आपदा आई है तो इन दो सालों में गुजरात के लोगों ने जो कांट्रिब्यूट किया है उसमें से कुछ हिरसा उन्हें इमिजिएटली देना चाहिए ताकि वहां की सरकार यह काम ठीक ढंग से कर सके। रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलीटेशन इन तीनों चीजों की तरफ सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा, तब जाकर यह काम पूरा हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं डिजार्स्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। आपके स्टेटमेंट में, बयान में यह कहा गया कि डिजार्स्टर क्राइसेस मैनेजमेंट के लिए यह कमेटी बनाई गई है। मुझे नहीं मालूम कि उस कमेटी ने कोई प्रोग्राम भी बनाया है या नहीं बनाया है? क्योंकि जिस तरह से वहां देखा जा रहा है, जिस तरह की न्यूज आ रही है, वहां के लोगों के जिस तरह से टेलीफोन आ रहे हैं उससे मैं नहीं समझता कि सही दिशा में प्रोग्राम चल रहा है। आपने क्या प्रोग्राम बनाया है? कोई टाइमबाउंड शेड्यूल है या नहीं? कम से कम यह तो हमें बताएं कि कब तक टेंट मिल जाएंगे? कब तक टेम्परेरी शैल्टर्स मिलेंगे? कब तक लोगों को रोजगार मिलेगा? वहां पर वालेंटरी एजेंसीज काम करने के लिए तैयार हैं,

एनजीओज काम करने के लिए तैयार हैं। एडाप्टेशन की पालिसी 20 दिन के बाद सरकार ने एनाउन्स की। 50-50 परसेंट में कर सकते हैं। 50 परसेंट वह देंगे और 50 परसेंट राज्य सरकार देगी या जो कोई वालेंटरी आर्गनाइजेशन या कोई राज्य सरकार इसको 100 परसेंट में करना चाहे तो वह इसको कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के दो गांव महाराष्ट्र सरकार ने एडाप्ट किए। मशीनरी वहां जाकर लगा दी, उनका स्टाफ वहां जाकर बैठ गया लेकिन वहां मलबा पड़ा हुआ है। वहां पर उनके लिए नया गांव बसाना है जिसके लिए उनको जमीन की जरूरत है। लेकिन उन लोगों को आफिशियल लेटर नहीं मिला है। वह लैंड कहां होगी, वह जमीन कब तक मिलेगी उनको मालूम नहीं और वे वहां पर बैठ हुए हैं। यही हालात एनजीओज की है। वालेंटरी एजेंसीज को जिस तरह से आफिशियल लेटर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। वहां पर जवाहरनगर को एडाप्ट करने की बात थी। मशीनरी ले जानी थी लेकिन तीन दिन तक उनको परमीशन नहीं मिली। वहां उनकी मशीनरी आदि पड़ी है लेकिन जो उनको आफिशियल लेटर मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो निर्णय लेने हैं मेरे ख्याल में इमीडिएटली ले ले ताकि जो एनजीओज, वालेंटरी आर्गनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट काम करना चाहती हैं वह अपना काम कर सकें।

वहां पर जो इंडस्ट्री और कामर्स में लगे हुए लोग हैं, खासतौर से गांधीधाम, काडला और बाकी जगहों पर वे आकर हम से मिले थे। वे कहने लगे कि बाहर से आकर हम लोगों ने यहां पैसा लगाया हुआ है लेकिन यह ड्राउट प्रोन एरिया है, कभी यहां पर साइक्लोन आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है और कभी सूखा पड़ जाता है इसके कारण हमको नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए कम से कम एक ऐसा पैकेज एनाउन्स किया जाए जिसमें पांच साल के लिए, दस साल के लिए टैक्स होली-डे का प्रावधान हो या फिर हमें साफ्ट लोन मिले या कुछ और ऐसे इंसेंटिव मिलें जिस तरह से नार्थ-ईस्ट, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को दिया जाता है जिससे कि हम अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? कल गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एनाउन्समेंट की थी। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा लेकिन सेट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इटरेस्ट ले और इस पर विचार करे कि कैसे इन लोगों को टैक्स एक्जम्पशन के लिए इंसेंटिव मिले। कच्छ के साथ साथ सौराष्ट्र इलाको और नार्थ गुजरात की कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि जो पैकेज कच्छ के लिए दिया गया वही पैकेज इन एरियाज के लिए भी होना चाहिए।

जहां तक कमजोर बिल्डिंग का सवाल है, इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने कार्यवाही शुरू की है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर बिल्डर इमारत की फाउन्डेशन अच्छी रखते, बिल्डिंग की नींव अगर कमजोर नहीं होती तो इतनी बिल्डिंग कभी नहीं गिरती। साथ वाली बिल्डिंग तो इनटैक रही लेकिन उनके साथ वाली बिल्डिंग ढह गई क्योंकि मिली भगत है जिस तरह का बिल्डिंग मैटीरियल यूज करना चाहिए, जिस तरह का डिजाइन बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। तो कम से कम इसके बारे में कानून बनाकर, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इश्योरेंस की बात है। कुछ कार्यवाही इश्योरेंस के बारे में हुई है। लेकिन ऐसा न हो कि जिनका इश्योरेंस है उनको भी कई सालों तक इश्योरेंस न मिले। कुछ लोगों का इश्योरेंस था ही नहीं तो उसके बारे में क्या करना है इसके बारे में मेरा ख्याल है कि मंत्री जी और सरकार सोचेंगी।

अखबार में पढ़ रहे थे कि खासतौर से केलामिटी रिलीफ फंड और नेशनल फंड जो है, कई स्टेटों ने इसको डाइवर्ट किया है या एडमिनिरट्रेटिव एक्सपेंसेज के पर्षज के लिए उसका इस्तेमाल किया है। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, उनको कम से कम आइडेंटिफाई करना चाहिए। गुजरात में भी इस फंड को डाइवर्ट किया गया है। अगर यह पैसा वहां होता जो यह डिजास्टर हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा वहां हुई है, उस काम में वह आता। इसमें भी काफी रिट्रक्ट रहने की जरूरत है।

डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम कई सालों से कर रहे हैं। उड़ीसा का हादसा हुआ। वहां पर जिस तरह से साइक्लोन आया और जिस तरह से नुकसान हुआ उसके बाद काफी समय हमें बीच में मिला। अगर उसके बारे में कुछ करते, वहां से कुछ सबक सीखते तो हमें लाभ मिल सकता था। लेकिन कुछ सोचा नहीं गया, कुछ किया नहीं गया। यह अर्थ-व्येक जो गुजरात के आया है इसके बाद इसमें तेजी आनी चाहिए और जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनने जा रहा है, जो कमेटी बनी है वह इसके लिए प्रोग्राम बनाए ताकि आने वाले दिनों में, खुदा न करे कि ऐसा कोई हादसा हो लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा हो तो उसके लिए ठोस कदम उठा सके।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि काम बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ मैं गुजरात के बारे में यह कहना चाहता हूं कि : "हाथ वह लोग जो कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ है, एक हम हैं गुजराती, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं"। मान्यवर, लेकिन हमें फिर भी दया, भीख या सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हालत ने हमें ऐसा बनाया है। फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं, हम हौसलामंद लोग हैं, खुदार भी हैं, मेहनतकश भी हैं सिर्फ कुछ दूर तक हमारा साथ दीजिये, हाथ पकड़िये, बाकी मंजिल हम अपने आप तय कर लेंगे और किशती को जरूर किनारे लगाएंगे। सिर्फ हमें आपका साथ चाहिये।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): पूरा देश आपके साथ है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to announce that this discussion has been converted into a Short-Duration Discussion. Accordingly, two-and-a-half hours have been allocated for the discussion. मंत्री जी आपको लोक सभा में कब जाना है?

श्री नीतीश कुमार : चार बजे मैडम।

उपसभापति : आपको जवाब देने में कितना समय लगेगा?

श्री नीतीश कुमार : वहां स्टेटमेंट देना है।

उपसभापति : आप रियेक्ट तो करेंगे सब लोग इतना भाषण कर रहे हैं। आपको 15 मिनट काफी हैं? Mr. Minister, when should we conclude the discussion, to free you before 4 o'clock?

श्री नीतीश कुमार : मैडम स्टेटमेंट देना है और उसके बाद हाऊस में वहां चर्चा भी होने वाली है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. Would you need 15 minutes to answer the debate? You should be relieved from here at 4 o'clock.

SHRI NITISH KUMAR: Madam, I will need half-an-hour. I have to make a statement there at 4 o'clock. Discussion may take place there.

श्री के. रहमान खान (कर्णाटक): वहाँ तो क्लेरीफिकेशन नहीं हैं, स्टेटमेंट दे कर के आ सकते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will have to go to the Lok Sabha at 4 o'clock to start the discussion there, whether he makes a statement or some other discussion takes place. The main thing is he has to be relieved from here before 4 o'clock.

श्री संघ प्रिय गौतम : चार बजे तक डिस्कशन कर लेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We should try to conclude the discussion by 3.30 p.m. Therefore, I would request you to make your speeches accordingly.

SHRI LALITBHAI MEHTA (Gujarat): Madam, he can go there at 4 o'clock and then come back.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He cannot do so. He has to sit there.

SHRI LALITBHAI MEHTA: Madam, at 3.55 p.m. he can leave this House. After some time, he can come back.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please try to understand what I am saying. You don't listen to me. वे खुद वहाँ बैठ कर डिस्कशन को पायलट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ शार्ट ड्युरेशन डिस्कशन हुआ वहाँ भी होने वाला है।

SHRI LALITBHAI MEHTA: Madam, my friend, Shri Ahmed Patel, has taken more than 30 minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: His party has got 36 minutes. If he has taken 30 minutes, he has still taken five minutes less. He was within his time. He gave a complete picture of it. Now Shri Dave will speak.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : उपसभापति महोदया, ...

श्री संघ प्रिय गौतम : पांच मिनट में खत्म कर देंगे। ... (व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्यों? ... (व्यवधान)...

उपसभापति : यह आपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। यह मेरा प्रावधान नहीं है। इनसे आप बात कर लीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : माननीया उपसभापति महोदया, जो घटना कच्छ में और गुजरात में हुई है मैं उसी प्रदेश से आ रहा हूँ। मैंने कई बार यह मसला कच्छ के बारे में इस हाऊस में पहले भी उठाया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात के मायने क्या हैं। यह तीन रीजन, Kutch is not a district. Kutch is a region. कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात को मिला कर के गुजरात बनता है। 45 हजार स्क्वायर किलोमीटर कच्छ रीजन का एरिया है। इस भूचाल की वजह से गुजरात का हर गांव, हर बड़ा टाउन सब ध्वस्त हो गया है। पहले 1819, 16 जून को पहली बार भूचाल आया था। उस समय 8 आरसी का था। उससे सारी जमीन और पानी का बदलाव हो गया। अकाल तब से ही शुरू हुआ। पहले सिन्धु नदी का पानी कच्छ तक आता था, वही से बंद हुआ। फिर 1956 में भूचाल आया। जो अभी अंजार में बड़ी घटना घटी। उसी अंजार शहर का एक भाग उसमें चला गया। फिर 2001, 26 जून को 6.9 आरसी का भूचाल आया। अहमद साहब ने जो कहा मैं उस घटना में नहीं जाऊंगा। हमारे कितने दोस्त, यार, मित्र, संबंधी, वर्कर्स, नजदीक के लोग सब चले गए। करीब 183 छोटे गांव बिल्कुल ध्वस्त हो गए। 4 सौ से ज्यादा गांवों में मोर दैन 70 परसेंट नुक्सान हो गया। बाकी जो गांव बचे हैं उनमें भी कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें दरार न पड़ी हो, कुछ न कुछ छोटा मोटा नुक्सान नहीं हुआ हो। हर तहसील में लोग मरे हैं - कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन 45 हजार स्क्वायर किलोमीटर में यह नुक्सान हुआ है। यह जो कह रहे थे, सही बात कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल काम है। राज्य सरकार के सामने एक बड़ा मुश्किल काम था। मैं हर वक्त यहां जब स्पेशल मेशन आदि से हाऊस का और सरकार का ध्यान खींचता था तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि कच्छ के लोगों को और कच्छ को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि सारी दुनिया और देश का ध्यान कच्छ पर जाएगा। हमने बहुत बड़ी कीमत चुकायी है। इसीलिए अब जो घटना घट गयी, घट गयी, जो हो गया सो हो गया। प्रिंसली स्टेट में भी हमारे कच्छ का एक मोटो था - courage and confidence. उसके मुताबिक यहां के लोग आज भी दुनिया भर में बस रहे हैं। दुनिया भर में कच्छ के लोग व्यापार-धंधा कर रहे हैं।

घटना इतनी गंभीर है। ये कह रहे थे कि रेस्क्यू नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब पौने नौ बजे यह घटना घटी, भुज के सारे हास्पिटल, सिविल हास्पिटल जमीन के अंदर चले गए। आप उनकी छत पर हाथ लगा सकते थे। सारे हास्पिटल्स चले गए। डाक्टर, नर्सज, पेशेंट्स सब चले गए। 5-10 मिनट में तो हजारों लोग गांवों में से हास्पिटल पहुंच गए। किसी की टांग टूटी थी, किसी का हाथ टूटा था, किसी के सिर पर चोट लगी थी। ऐसी हालत थी कि कहां उनका इलाज हो। तो भी वहां के लोकल डाक्टरों ने, दूसरे डाक्टरों ने वहां जुबिली जो एक प्ले ग्राउंड था उसमें तात्कालिक हास्पिटल खड़ा करके उनकी दवा दारु की। स्पेशल प्लेन्स से जो सीरियस थे ऐसे कई लोगों को मुम्बई, कई लोगों को पुणे, कई लोगों को अहमदाबाद आदि सब जगह भेजा। वे ऐसी बात कह रहे हैं कि रेस्क्यू नहीं हुई। ताज्जुब की बात है। उसी वक्त रात तक तो सैकड़ों, हजारों पेशेंट्स बाहर चले गए। दूसरे तीसरे दिन सब रेस्टोर हो गया। बाहर से लोग आए, दुनिया भर से लोग आए। हास्पिटल लेकर आए, स्पेशल प्लेन्स से आए ... (व्यवधान) ...

देखिए मैडम आप डिस्टर्ब मत करिए। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हमारे दिल में दर्द है। हमने बहुत कुछ खोया है। ऐसी घटना ईश्वर कहीं भी नहीं करे। हमने बहुत खोया है। लेकिन जो कुछ हुआ है वह मैं कह रहा हूँ। अहमद जी ने सही बात कही। तीन-साढ़े तीन गो कच्चा ध्वज लेकर जा रहे थे, जमीन गिर गयी,

दोनों तरफ से सारे मकान गिर गए और वे दब गए। कोई अच्छी घटना नहीं थी। हमारे सबके लिए दुखद घटना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू नहीं हुई। अभी भी टी.वी. में लोग बताते हैं। भुज की इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि एक मकान पूरा आधा गिर गया, दो मकान आधे गिर गए, पीछे के दो मकान सम्पूर्ण गिर गए और उनके आगे दो मकान खड़े हैं। उनको जैसे भी हो लगाना है। थोड़ा सा सोचिए। जैसे भी लगाना है तो जो आगे मकान खड़े हैं उनको भी गिराना है। उनका मालिक कहां चला गया, कहां रहता है, किसी को पता नहीं है। उसका सामान उस घर में पड़ा है। उसका सामान उस घर में पड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास यह एक बड़ा सवाल है कि कैसे करें, क्या करें। बहुत मुश्किल काम है। आपने सही कहा है कि यह एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैडम, मैं कह रहा हूं कि जो हो गया, सो हो गया। राज्य सरकार ने कल अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी डिक्लेयर कर दी है। गांवों के लिए पालिसी डिक्लेयर हो गई है। अब हमारी बारी है। यह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर पर स्थित डिस्ट्रिक्ट है। 51 सालों में इस कच्छ डिस्ट्रिक्ट ने 32 अकालों का सामना किया है, दो साइक्लोन और एक भूचाल आया है। बारिश कम हो रही है। पांचवें जोन में यह डिस्ट्रिक्ट आता है। अभी वहां कोई बड़ी इंडस्ट्री आएगी ही नहीं। कभी नहीं आने वाली है क्योंकि यह पांचवें जोन के अंदर है। रह गई स्माल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, वह इंडस्ट्री वहां आ सकती है। वहां बारिश होती नहीं है, यदि होती भी है तो बहुत कम होती है। ऐसी परिस्थिति में अब इस प्रदेश के सारे लोग हतप्रभ हो गए हैं। उनकी इकोनोमी रिवाइव करनी है। रिवाइव कैसे करेंगे, लोग अपने रोजगार व धंधे कैसे शुरू करेंगे? बाजार सब गिर गए हैं। वहां कुछ नहीं है। सब लोग बाहर बैठे हैं। वे गांवों से बाहर आ गए हैं। वहां छोटे-छोटे गांव हैं। उनके घर व मकान सब गिर गए हैं। वे भी बाहर ही रहते हैं। सारी इकोनोमी रिवाइव करने के लिए हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार विचार कर रही है और अब हम लोगों को यह सोचना है। अब यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, कंबल नहीं दिए, कहीं टेंट नहीं मिले, कहीं वह नहीं मिला, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ मिला है। ऐसा कह कर मैं अन्याय करूंगा कि हमने वहां पर लोगों को 100 प्रतिशत मदद पहुंचाई है। कमी भी होगी, लेकिन यह बात अब करने की जरूरत नहीं है। अब हमको यह करना है कि देश का एक भाग, जो कि बॉर्डर का एक इलाका है, बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी इकोनोमी को कैसे रिवाइव करना है। हम लोगों को बैठकर इस बारे में सोचना है। यह हम सोचेंगे तो देश के एक भाग के साथ, देश के एक कोने में पड़े हुए एक भाग के लोगों के साथ हम न्याय करेंगे। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि बॉर्डर पर स्थित इस कच्छ डिस्ट्रिक्ट के तीन भाग हैं, वेस्टर्न पॉर्ट, मिडल पॉर्ट और ईस्टर्न पॉर्ट। वेस्टर्न पॉर्ट में पहले से बारिश न होने की वजह से लोगों के माइग्रेशन होने से वहां पर आबादी कम हो रही है। यह कई बार मैंने इस हाउस में भी कहा है कि वहां पर आबादी बसाओ। वहीं से घुसपैठ हो रही है। कई बार मैंने चिल्ला-चिल्ला कर इस हाउस में कहा है कि वहां की आबादी के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, क्योंकि वहां से लोगो का माइग्रेशन होता जा रहा है। अब मिडल पॉर्ट में भूचाल आ गया, तो कहीं वहां से भी माइग्रेशन शुरू न हो जाए, यह हमें देखना है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इस बारे में हम सब लोगों को साथ में बैठकर विचार करना पड़ेगा कि इस प्रदेश के मिडल पॉर्ट का यदि माइग्रेशन हो गया तो बाहर के देशों के लिए आसान हो जाएगा कि यहां से हम अंदर चले आए। मेरी सरकार से रेक्वेस्ट है और मैं आपको दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आप वहां पर एक्साइज फ्री कर दीजिए। वहां पर जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो वहां पर बाहर से सीमेन्ट, स्टील, कोल आदि इंपोर्ट होगा। जो कुछ भी हो आप एक्साइज फ्री कर दीजिए।

सरकार ने ग्राम विस्तार के एडाप्शन के लिए तीन फेज लिए हुए हैं। वहां बहुत पैसे खर्च जायेंगे और प्रदेशों से बहुत मदद भी आई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां आए थे। उन्होंने भी पैसे के बारे में कहा है कि कोई चिंता मत करिए, इस प्रदेश को पूरी-पूरी सहायता मिलेगी। हमारी गुजरात सरकार ने कल इंडस्ट्रियल पालिसी डिक्लेयर करके सब कुछ बता दिया है। पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो कानूनी बातें हैं वे हमको तय करनी पड़ेंगी और वे यहां से तय होंगी। वेस्टर्न पोर्ट में, जैसे भावनगर में शिप ब्रेकिंग यॉर्ड है। एक शिप ब्रेकिंग यॉर्ड जखु पोर्ट के पास खड़ा किया जाए। माइनर पोर्ट राज्य सरकार के साथ और शिप ब्रेकिंग यॉर्ड सैन्टर के साथ मिल-बैठ कर तय करके शुरू किया जाएगा तो आबादी वहां बढ़ने लगेगी। कच्छ का 450 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। इतना बड़ा समुद्री किनारा कहीं भी नहीं है। मैडम, आजादी के पहले प्रिंसली स्टेट में मांडवी पोर्ट एक फ्री पोर्ट था और वहीं से सारे कच्छ की इकॉनोमी चलती थी। मैडम, आज फिर वह दिन आ गया है। आप मांडवी पोर्ट को फ्री पोर्ट डिक्लेअर कीजिए और दूसरे यहां स्पेशल इकॉनोमिक जोन डिक्लेअर कीजिए। आप सब को मालूम होगा कि यह एस.ई.जेड. का फॉर्मूला चाइना पैटर्न पर है, लेकिन मैं फ्री पोर्ट की यहां बात कर रहा हूं। मैडम, दुबई में जबलली पोर्ट है। यह पोर्ट वहां सन् 85 में शुरू हुआ था। आप जबलली पैटर्न पर कच्छ के एरिया को फ्री पोर्ट डिक्लेअर कीजिए। जबलली पोर्ट में आज दुनिया भर के देश - चाइना, यू.के., यू.एस. की कंपनियां हैं और जब आप कच्छ में भी जबलली पैटर्न पर फ्री पोर्ट डिक्लेअर करेंगे तो मैं मानता हूं कि दुनिया के सब देश इस विस्तार में धंधा करने के लिए आएंगे। मैडम, इस विस्तार के लोगों को थोड़ासा आश्वासन चाहिए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं या हम ऐसा आप के विस्तार में शुरू करेंगे। ये करेज वाले लोग हैं, ये फिर से खड़े हो जाएंगे और सब साथ मिलकर ये अपने धंधे में जुट जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे थोड़े से कदम उठाइए ताकि इस विस्तार के लोग फिर से खड़े हो सकें।

अभी अहमद जी ने कहा कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। मैडम, यह डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। गुजरात भी देश का एक भू-भाग है, लेकिन 80 प्रतिशत नुकसान कच्छ में हुआ है। मैं कहता हूं कि अहमदाबाद और सौराष्ट्र में जान-माल की हानि हुई है, वहां भी सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन जहां पर सब से ज्यादा नुकसान हुआ है, उस को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। हमने नॉर्थ ईस्ट को भी स्पेशल पैकेज दिया है, इसी तरह कच्छ को भी स्पेशल पैकेज दीजिए। आप यह इनकम टैक्स और करस्टम ड्यूटी के बारे में दो दिन बाद आने वाले जनरल बजट में अनाउंस कीजिए। वहां की राज्य सरकार ने तो अपनी पॉलिसी डिक्लेअर कर दी है। मैडम, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ - मैं इस में नहीं जाना चाहता। वहां बहुत सी स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं जिन में आर.एस.एस., विश्व हिंदू परिषद् और मुस्लिम संस्था भी हैं। ये सब साथ मिलकर काम कर रही हैं और एक लंगर पर सभी लोग भोजन भी करते हैं। यह मैं ने स्वयं देखा है। मैं 19 तारीख तक वही था। ये सब लोग एक लंगर पर साथ खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में रहते हैं और किसी का किसी के साथ फरियाद नहीं है। लेकिन कभी-कभी टी.वी. पर लोग बता देते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ या हमारे पास कोई कार्यकर्ता नहीं आया। वहां शुरू में जब टी.वी. वाले गए होगे तब नहीं हुआ होगा, वह सही बात है। जेल से कैदी भाग गए, यह सही बात है। भुज की जेल टूट गयी तो कैदी भाग गए। वहां एअर फोर्स के 102 जवान मारे गए, उन के भी मकान टूट गए, यह भी बात सही है। मैडम, यह बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और मैं इस के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने वहां सारी मशीनरी लगा दी है। वहां दो, तीन दिन बाद 22 करोड़

रुपया कैश डाल बांटा गया है। वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी भी जल्द-से-जल्द रिस्टोर हो गयी थी। मेरी एक ही शिकायत थी कि टेलिफोन की सेवा 5-7 दिन बात मिल पाई क्योंकि सारा टेलिफोन का ऑफिस गिर गया था और उन के भी 7 लोग मर गए जोकि ड्यूटी पर थे, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपनी सेवा नहीं दी जबकि मैं ने सुना है कि उन का गवर्नमेंट के साथ ऐसा एग्रीमेंट होता है कि उन्हें यह सेवा देनी चाहिए। वहां 'सेल फोन' और 'ए.टी.एन.टी.' ने यह सुविधा नहीं दी। मैं मानता हूँ कि इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। सारी दुनिया से हम पांच दिनों तक कट गए। उन लोगों के पास ऐसी सुविधाएं हैं कि छोटे-छोटे एंटीना लगाकर वे 24 घंटे में उसे शुरू कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, यह मेरी शिकायत है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टेलिफोन सर्विसिज थी, उनके सारे आफिस जमीन में चले गए, वे कैसे काम करेंगे। वहां कई सरकारी आदमी जो ड्यूटी पर थे वे मर गए, कई लोगों के परिवार के लोग भी मर गए, उनके घर टूट गए, ता भी वे काम पर आए, वे काम में लग गए, जुट गए और दुनियाभर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस प्रदेश की बहुत मदद की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हमको बहुत साथ मिला है, बहुत सुविधाएं मिली हैं, बहुत डाक्टर्स आए हैं, दवाइयां मिली हैं। यह सीनियर हाउस है, ऐल्डर्स हाउस है, हम आज साथ में बैठकर यह सोच सकते हैं, हमारे पास आज समय है कि भारत के एक प्रदेश, एक भाग की इकॉनमी कैसे रिवाइव हो। इस मुद्दे पर हम सब लोग एक हो जाएं कि यह इकॉनमी रिवाइव करनी है, खड़ी करनी है और लोगों को काम पर लगाना है। जगमोहन जी वहां आए थे, उनके सारे अफसर वहां आए थे, इंजीनियर जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, वे भी आए थे, सब देख रहे हैं कि पांच जोन के मकान कैसे बनें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सब देख गए हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जिनकी डेट लग गई, उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा काम है, मुश्किल काम है। आप चार-पांच बार एक शब्द बोले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा काम है, मुश्किल काम है और ऐसे में इस ऐल्डर्स हाउस से मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस प्रदेश से मैं आया हूँ, हमने बहुत कुछ वहां खोया है, बहुत कुछ गंवाया है - हमारे मित्र, हमारे वर्कर, हमारे रिश्तेदार - मेरे से बोला नहीं जाता है कि मैं आज इस हाउस में क्या बोलूँ, हम लोग साथ मिलकर इस प्रदेश को खड़ा करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदया, इसे महज एक संयोग कहें, संकेत कहें या सबक कहे कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए हमारे गणतंत्र दिवस को चुना। गणतंत्र दिवस की वह सुबह जब हमारा गणतंत्र अपनी 50 वर्षों की उपलब्धियों और शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक धरती कुछ इस तरह हिली कि गुजरात के जीते-जागते शहर देखते ही देखते श्मशान में तब्दील हो गए। बड़ी-बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह मिट्टी के ढेर में बदल गईं। चारों तरफ हा-हाकार, चीखें और मौत का तांडव था और एक बार के लिए प्रकृति की इस विनाश-लीला के सामने लग रहा था कि इंसान कितना निःसहाय है। लेकिन, महोदया, इंसान की यह अदम्य जिजीविषा ही होती है कि वह विनाश के बाद भी तिनका-तिनका जोड़-जोड़ कर फिर अपना घर बना लेता है और आदमी की इसी अदम्य जिजीविषा के बारे में कहा गया है कि :-

जो जीवन की धूल घाट कर तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है,

जिसने सोने को खोदा, लोहे को मोड़ा है,

जो रवि के रथ का घोड़ा है,

वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा।

उपसभापति महोदया, इस महाप्रलयकारी भूकम्प की तीव्रता को तो रिएक्टर स्केल पर मापा जा सकता है लेकिन इस भूकम्प ने जो भयावह तबाही, बर्बादी और कहर इंसानी जिंदगी पर बरपाया है, उसे किसी स्केल पर नहीं मापा जा सकता, इसे तो सिर्फ दर्द के रिश्ते से समझा जा सकता है और दर्द का यह रिश्ता ही था कि जिसने न सिर्फ हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर, बल्कि विदेशों तक भी गुजरात के लोगों की चीखों को पहुंचाया और तत्काल मानवता उनके साथ खड़ी हो गई।

उपसभापति महोदया, देश-विदेश सभी जगहों से तत्काल राहत-टीमें गुजरात पहुंचनी शुरू हो गई थी, लोगों की आंखों से कोई कण्ठ बाकी नहीं छोड़ी गई। राहत सामग्री की कोई कमी नहीं थी, महोदया, अगर कमी कहीं थी तो वह कमी थी प्रशासनिक कुशलता की, प्रशासनिक तत्परता की, जिसकी कि इस संकट की घड़ी में किसी भी राष्ट्र को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। महोदया, किसी भी राष्ट्र की शक्ति की पहचान संकट की घड़ी में होती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संकट की इस घड़ी में, उस दर्दनाक घड़ी में गुजरात की सरकार पूरी तरह असफल और नाकारा साबित हुई। महोदया, यह बात मैं अखबारों के हवाले से नहीं कह रही हूँ, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारी जो टीम गुजरात गई थी, उसने यह सब अपनी आंखों से देखा है और सुना है। एक तरफ तो राहत-सामग्री के पहाड़ों के ढेर लगे हुए थे और दूसरी तरफ मैंने इन आखों से भूख से तड़पते हुए और पानी के लिए बिलखते हुए लोगों को देखा है। मैंने उन चेहरों के आक्रोश को भी देखा है और उन आंखों के आंसुओं को भी देखा है जिन्होंने अपने आत्मीयजनों को मलबे के नीचे तिल-तिलकर मरते हुए देखा है।

महोदया, अगर अहमदाबाद जैसे शहर में 36 घंटे तक, 48 घंटे तक राहत नहीं पहुंचती है, कोई बचाव टीम नहीं पहुंचती है तो इसे क्या कहा जाए? महोदया, भुज की स्थिति तो कल्पनातीत थी। वहां शहर के शहर, गांव के गांव कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे, चारों तरफ मौत का तांडव था। ऐसे में मुख्यमंत्री भविष्यवाणी कर रहे थे, मैं तो कहूंगी कि भविष्यवाणी के जरिए आतंक फैला रहे थे कि आगामी 48 घंटों में इसी तरह का भूकंप फिर आ सकता है। महोदया, इस तरह के बयान का उस समय क्या औचित्य था? इस तरह का बयान देने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ इतना ही निकला कि उस समय गुजरात सरकार बिल्कुल पंगु हो गई थी। अधिकारी लोग अपने ही परिवारों को संभालने में लग गए और पीड़ित लोगों को जो राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत थी, वह उन तक नहीं पहुंच पाई। महोदया, अगर अंजार, भचाऊ और भुज जैसे जगहों में समय पर राहत नहीं पहुंच पाई तो इसका कारण यही था।

महोदया, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो जो विदेशी टीमें वहां पर आई थी, नार्वे की टीम ने हमें बताया कि हम सबसे बड़ी टीम लेकर आए हैं, दवाइयां लेकर आए हैं लेकिन हम वहां पर बैठे हुए हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमें कहां जाना है और कैसे काम शुरू करना है। महोदया, फ्रांस की टीम भी वहां पर आई हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि हम कब से वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हम कहां जाएं और क्या करें। वे 36 घंटे बाद भुज में पहुंचे। चूंकि प्रधानमंत्री को भुज जाना था, इसलिए वह समन्वय अधिकारी जिसका यह दायित्व था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको वह कोऑर्डिनेट करता, वह अपना काम छोड़कर प्रधानमंत्री के दौरे संबंधी व्यवस्था में लग गया। मैं समझती हूँ कि इसके चलते राहत कार्यों में रुकावट पहुंची है।

महोदया, जहां-जहां भी हमारी टीम पहुंची, हमसे कहा गया कि आप ही पहले व्यक्ति हैं जो हम तक पहुंचे हैं। इस प्रकार हर जगह गुजरात सरकार की अकर्मण्यता और नाकाबलियत नजर आ रही थी। इसके साथ ही इस भूकंप में गुजरात सरकार की प्रशासनिक मशीनरी और केन्द्र सरकार के आपदा प्रबंधन की पोल खुलकर सामने आ रही थी।

महोदया, हमारी टीम ने जो तथ्य एकत्रित किए हैं, वे इसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अहमदाबाद में भूकंप के झटकों से कहीं ज्यादा बड़ा झटका भ्रष्ट बिल्डरों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों की तिकड़ी ने पहुंचाया है। महोदया, अहमदाबाद में जो रिहायशी बहुमंजिली इमारतें धराशायी हुई हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी थीं जो पिछले 2-3 सालों में बनी थीं। सारे कायदे और कानूनों को ताक पर रखकर, घटिया सामान का इस्तेमाल करके, ये इमारतें बनाई गई थीं और लोगों की जिंदगी के लिए जो ये तथाकथित बसेरे बनाए गए थे, वे बसेरे ही लोगों की कब्रगाह में तब्दील हो गए।

महोदया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पटेल जो खुद एक बिल्डर हैं और भाजपा की राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष हैं, वे स्वयं भवन निर्माताओं से चंदा उगाहने का काम करते हैं और बदले में उन्हें तमाम गैरकानूनी कामों को करने की छूट दे देते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भूकंप के दो महीने पहले राज्य सरकार ने सभी गैरकानूनी इमारतों पर इम्पैक्ट फी लगाकर इनको कानूनी कर दिया लेकिन जब बिल्डर्स ने शोर मचाया कि यह इम्पैक्ट फी बहुत ज्यादा है तो बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम इम्पैक्ट फी कम कर देते हैं, आप जैसे राजी रहें, वह ठीक है। महोदया, इनका लोगों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। तो महोदया, अब यह काम चल रहा है कि जो इमारतें धराशायी हो गई हैं उनको भी क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है कि इनके निर्माण में कहीं कोई खराबी नहीं थी। महोदया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है -

"Building mafia erects a wall for cops." The report says, I quote, "Is the Ahmedabad Urban Development Authority (AUDA) trying to cover its tracks? After so many lives were lost because of unscrupulous builders and conniving officials, the agency is yet to hand over the records of the constructions to the police."

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है -

"The file of Shikhar Apartments, where 98 persons were killed, has just four sheets of paper. The file of Mansi Complex, in which 33 persons were killed, has nine papers. The files of Akshar Flats and Himgiri Apartments; too, are similarly thin."

तो महोदया, यह है और अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि-

"I do not know what to do with these papers."

तो यह तो हाल है। महोदया, अपनी आंखों से मैंने देखा था कि जिस इमारत का नाम, कभी-कभी प्रतीक भी किस तरह अर्थ देते हैं हमें, जिस इमारत का नाम 15 अगस्त एवेन्यु रखा गया था वही इमारत इस भूकम्प में 26 जनवरी को पूरी तरह धराशायी हो गई और जिस दिन हम वहां 31 तारीख को पहुंचे उस दिन भी उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे अनगिनत लोग दबे पड़े थे। वहां चारों तरफ के लोग हमें बता रहे थे कि हमें पता नहीं है कि कितने लोग इसके नीचे दबे हुए पड़े हैं। महोदया, राजधानी अहमदाबाद की यह स्थिति थी। वहीं पर एक बंगाली महिला जो कुछ ही महीने पहले वहां रहने आई थी उसने बताया कि मेरी सास अंदर मरी पड़ी है, मैं नहीं जानती कि उसको कैसे निकाला जाए। महोदया, वहां पर सेना के एक मेजर मन्था थे जो वहां काम करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि यह बिल्डिंग एक करोड़पति की है और आज इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद वह महाशय अभी तक यहां पर एक बार भी नहीं आए हैं, कम से कम मानवता के नाते तो उन्हें यहां पर आकर देखना चाहिए था। पता नहीं, वे कहां हैं। लोगों में इतना आक्रोश सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति है। वे कह रहे हैं कि यही वे लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। प्रकृति ने हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया इन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते हमारे साथ यह हुआ है।

महोदया, इसी बिल्डिंग के पास में भाजपा के एक सांसद हरेन पाठक का घर था। लोगों में आक्रोश था कि वे वहां पर आए भी नहीं हैं। महोदया, इसी तरह से शांतनु अपार्टमेंट हम देखने गए जो पूरी तरह मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका था।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदया, जो व्यक्ति यहां मौजूद ही नहीं है उसका नाम निकाल दिया जाए। वह हरेन पाठक का नाम ले रही हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इनके वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है। लोगों ने कहा है, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्री संघ प्रिय गौतम : कही हुई बात आथैंटिक नहीं है ... (व्यवधान) ... आप सिर्फ आलोचना कर रही हैं, आपको वहां के लोगों से कोई मुहब्बत नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : यह क्या बात कर रहे हैं आप? ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं अपनी जुबानी नहीं कह रही हूँ, केवल जो लोगों ने मुझे बताया है वही है। यह तो हमारे लिए सबक की चीज है। यह हमें सीखना है कि हम जो जनप्रतिनिधि बनते हैं यह हमारे लिए भी सबक की चीज है, यह किसी की आलोचना का प्रश्न नहीं है। अगर लोग संकट में फंसे हों तो जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व है, वह अपने दायित्व को जरूर समझें।

महोदया, मैं अपने ही अनुभव जो लोगों के जरिए मैंने जाने, उन्हीं का बयान कर रही हूँ ताकि हम लोग सबक ले सकें, इस तरह के संकट से हम सबक ले सकें और जनता को सही मायनों में ईमानदारी से राहत दे सकें और जनप्रतिनिधि का फर्ज पूरा कर सकें। इसमें किसी तरह की टीका-टिप्पणी का, आलोचना का प्रश्न नहीं उठता। महोदया, इसी तरह हम शांतनु अपार्टमेंट देखने गए जो पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया था। इस अभागी बिल्डिंग में 42 लोग दबकर मर गए। उपसभापति महोदया, वहीं मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम जयंती भाई पटेल था। महोदया, वह चार महीने पहले ही इस बिल्डिंग में रहने आए थे।

उनकी तीन बच्चियां इसमें दब कर मर गई। उस समय वह व्यक्ति कह रहा था कि -बहन जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह पीने 9 बजे भूकम्प आया और रात साढ़े 8 बजे तक मैं अपनी बच्चियों से बातें कर रहा था। मैं इतना असमर्थ हूँ, 'एक बाप के हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस मलबे में दबी हुई अपनी बच्चियों को निकाल सके क्योंकि उसके पास कोई हैवी अर्थ मूवर नहीं था। महोदया, जहां राजधानी अहमदाबाद में साढ़े आठ बजे तक कोई सहाय नहीं पहुंची और एक मां-बाप अपनी बच्चियों को कराहते हुए देखे तो यह हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है कि कौन-सा क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे पास में है, कौन-सी मशीनरी हमारे पास में है।

मैडम, मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां के लोग बहुत ही खूफा थे। लोगों में सरकारी मशीनरी के प्रति आक्रोश था। अहमदाबाद के साथ-साथ अंजार और भुज में 'तमाम बहुमंजिला जो इमारतें गिरी उनके पीछे भ्रष्ट बिल्डर्स का हाथ था।..

उपसभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, मैं समाप्त कर रही हूँ।

उपसभापति : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ीसी रियायत दे दें, मैं खत्म कर रही हूँ।

उपसभापति : बाकी के लोग भी हैं।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, महिला हैं, इनको थोड़ा-सा समय दे दीजिए।
...(व्यवधान)...

उपसभापति : या तो ये डिस्मिज्ड ले लें ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, महिला होने के नाते नहीं, मैंने जो वहां पर देखा है, जो त्रासदी हुई है उसको मैं बताना चाहती हूँ। इससे हम थोड़ा-सा सबक लें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. ...*(Interruptions)*... We have to manage the time also. We have to satisfy everybody. It is a great tragedy. बहुत ही भयानक घटना हुई है। उसके लिए हमें दो-दो, चार-चार मिनट के ऊपर हैगल नहीं करना चाहिए। वहां पर हजारों लोग अफेक्टिड हुए हैं। हाउस डिस्मिज्ड लेगा। मंत्री जी वहां चार बजे चले जाएं, उसके बाद कोई दूसरा मंत्री नोट्स ले ले, बाद में मंत्री जी आकर जबाब दे दें, ताकि इस पर सब लोग बोल सकें। जब सदस्य अपने दिल की बात कह रहे हों उस समय मैं घंटी बजाऊं यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहां हजारों लोग अफेक्टिड हो गए हैं और हम यहां कहें कि पांच मिनट, दो मिनट, एक मिनट का समय दे दीजिए, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, आपका सुझाव ठीक है। ...(व्यवधान)...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Madam, the Lok Sabha has also...*(Interruptions)*... After making a statement there, he can come back. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We cannot change it because they are also waiting for him. We have already started. ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: He can make a statement there and then come back. ...*(Interruptions)*... They can discuss it tomorrow. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: They have taken a decision. We should not interfere with the business of other House. ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Madam, this is a very serious issue. We belong to Gujarat. We have seen the whole tragedy. We want to speak something. If you keep it in both Houses on the same day and restrict the Members, I don't think it is fair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your leader decided it. Every party...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT : Madam, the Government should have kept it on two different days.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Bhatt *sahib*, don't argue with me on this subject because I have not decided it. ...*(Interruptions)*... Just a minute. Please sit down. Don't argue and waste the time. I am trying to help you out, but you are not trying to understand. The Lok Sabha people are also equally concerned. There Members from Gujarat in the Lok Sabha also. Moreover, it is not that only Gujarat people are concerned; the whole country is concerned. I am giving you a *via media*. Let the Minister go. Somebody else may take the notes. You want to express your concern. That will be expressed. Is it necessary that the Minister should be here? It is the joint responsibility of the Government. Anybody can take the notes. I am trying to find a way for you to speak freely. But that does not mean that you can go on speaking.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, कुछ मुद्दे रह गए हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। गुजरात के इस भयंकर भूकम्प ने हमें सबक दिया है कि वहां पर हमें कुछ चीजें और सीखने की जरूरत है। ये जो भ्रष्ट बिल्डर्स हैं, जो भ्रष्ट निर्माता हैं, उनके साथ राजनीतिज्ञ लोगो ने मिलकर, प्रशासन के लोगो ने मिलकर ये कर्मकांड किए, इनकी वजह से न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि भुज, अजमेर में भी इनकी बनाई बिल्डिंगें सबसे ज्यादा मौत का कारण

3.00 P.M.

बनी हैं और इसमें बहुत से राजनीतिज्ञ लोग शामिल हैं और अब इस पर लीपापोती की जा रही है। महोदया, अभी दवे साहब निर्माण की बात कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगी कि क्या भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हम गुजरात का नवनिर्माण कर सकेंगे? उपसभापति महोदया, हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आज जो करोड़ों करोड़ रुपया गुजरात में आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, देश से आ रहा है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रान्सपेरेंसी नहीं है कि कितना रुपया आ रहा है, उसका जनता के सामने कोई अकाउंट नहीं है। मैं पहली बात तो यह कहना चाहूंगी कि यह जो इतना रुपया आ रहा है उसमें पारदर्शिता बरती जाए। एक ऐसी मशीनरी बनाई जाए सभी पार्टी के लोगों को भिलाकर जो इस पर निगरानी रखे कि कैसे राहत का कार्य चलाया जाए। कि कहां कैसे राहत का कार्य चलाया जाए, यह बहुत जरूरी है। नहीं तो यही लोग - अभी रुपया आया नहीं और आप देख रहे हैं कि गुजरात में सभी निर्माण कार्यों के सामान की कीमतें बढ़नी शुरू हो गयी हैं और वही बिल्डर्स घाघ की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ गुजरात के भूकंप में जहां हमने मानवता के उच्चतम दर्शन किए, जहां लोग हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई - तमाम जाति के, रंग के, भाषा के, धर्म और मजहब के भेदभाव को भूलकर मानवता के नाते सहायता कर रहे थे, अहमदाबाद में वी.एस. अस्पताल में जब हम गये तो वहां के डाक्टरों ने मुझे बताया कि यहां अगर मुसलमान भाई नहीं आते, ईसाई भाई नहीं आते तो इतने लोगों की मौत हो जाती कि हम आपको बता नहीं सकते। मुसलमान लड़कों ने, ईसाई लड़कों ने अपनी जान की परवाह न करके - जब डाक्टरों ने कहा कि अब इससे ज्यादा खून नहीं दे सकते तो उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है। उन लोगों ने अपना खून देकर ...(व्यवधान)...

- श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड) : मैडम, क्या यहां धर्म के नाम पर प्रचार हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख - यह सब क्या है? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप सुन तो लीजिए, वह क्या कह रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इंसानियत कहां गयी थी? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इंसानियत के नाते ही मदद कर रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : धर्म का नाम ले रहे हो। ...(व्यवधान).... जाति का, धर्म का नाम आप बोलो कि वह अनुसूचित जाति का था, वह पिछड़ी जाति का था - वह ब्राह्मण था, वह छोटी जाति का था, यह सब क्या तमाशा है? ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात) : आपकी पार्टी के लोगों से जाकर पूछिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : कर्नाटक के मिनिस्टर ने सबसे पहले जो बकवास की, उसके कारण ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : और दूसरों ने खून दिया, उसका ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आखिर आप यह क्यों कहना चाह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आपको शर्म आनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपने क्या किया, वह भी सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : धर्म के नाम पर बात कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : अहलुवालिया जी, आप जब नयी पार्टी में गये हैं, वहां के लोगों
...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, please. Order.
...(Interruptions)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): आर.एस.एस. के लोगों का ठप्पा लगा हुआ है।
रिलीफ के रुपये पर आर.एस.एस. का ठप्पा लगा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसमें फिर विवाद कहां है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं?
...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down. Sit down. Please
take your seat.

I know that there are only three or four types of blood groups.
One is "O", then "A", "B" and "AB", plus or minus. From whichever person
of whichever religion it comes, the blood group has to be taken into
consideration. आप अपना भाषण खत्म करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, वही बात मैं कह रही थी कि जब मानवता का प्रश्न
आता है तो वहां इस तरह की बातें नहीं उठती। जहां इस तरह के उच्चतम आदर्श मिल रहे थे,
वहां पर हमें कुछ ऐसे काले पक्ष और शर्मनाक, क्रूर तथा बर्बर पक्ष भी देखने को मिले जिसको मैं
समझती हूँ कि हमें इस तरह के पक्ष नहीं चाहिए थे लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। मेरे साथी नहीं
मान रहे हैं लेकिन तमाम रिपोर्टें इस बात की गवाही देती हैं - चाहे आप 'हिन्दू' को देखिए, चाहे
आप 'फ्रंट लाइन' को देखिए कि जो नहीं होना चाहिए था, किन्तु दुर्भाग्य से राहत कार्यों में
साम्प्रदायिकता का रंग हमें देखने को मिला। वहां के वॉलेंटियर्स ने हमें बताया। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप गलत बोल रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह तो लिखा हुआ है। यह देखिए, सब लिखा हुआ है।
...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं बताता चाहता हूँ कि गुजरात में प्वाइंट 0.005 परसेंट से कम सिख रहते हैं लेकिन वहाँ सिखों ने लंगर लगाए, क्या वे जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर लगाए? वहाँ उन्होंने एक एक लाख आदमियों को एक एक बार में खाना खिलाया। ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा : सिखों के लिए तो एक भी शब्द नहीं कहा। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह 'हिन्दू' की रिपोर्ट है - "Still in the Limelight, Parivar Style" किस तरह वहाँ पर यह हुआ। यह अखबार है, आप इसे देखिए और लोगों ने भी बताया, अखबारों के हवाले में नहीं जा रही।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अखबार गलत लिख रहे हैं। अखबार देश में दंगा करवाना चाहते हैं, क्या आप भी करवाना चाहती हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : दंगा आप करवाना चाहते हैं। यह आपकी कोशिश थी। आप किसको कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : एक एक लाख आदमियों को खाना खिलाया। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): दंगे का सवाल मत उठाइए।

मौलाना ओवेदुल्ला खान आजमी (झारखण्ड): आपके हक में लिख दिया तो देश भक्त हो गए और उनके ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, वहाँ अखबारों में जो आ रहा है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : सरला माहेश्वरी जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया। आप कृपया बैठ जाइए, I will call other Member.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं खत्म कर रही हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can't permit you. You have taken enough time. अब आप खत्म कर दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, गुजरात की इस संकट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है और हर तरह कभी राष्ट्र पर संकट आए, कोई भी राष्ट्रीय विपत्ति आए पूरा देश को खड़े होने की जरूरत है। चाहे बंगाल की बाढ़ हो, उड़ीसा का तूफान हो तो यह सदन निश्चितरूप में जागना चाहेगा कि क्या हमने मानवता की अलग अलग कसौटियाँ बना रखी हैं? मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि गुजरात के संकट के नाम पर हमारे वित्त मंत्री अधिभार लगाने की बात कर रहे हैं और कड़े कदमों के लिए जनता को तैयार रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन खुद केंद्र सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं।

उपसभापति : अब आप बंद कर दीजिए। यह बात आप पहले ही कह चुकी हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं यह कहना चाहती हूँ कि जनता पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर अपना बकाया वसूल कर ले तो यह जनता पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। अंत में, मैं यह कहना चाहूँगी कि गुजरात की जनता के दुख दर्द के साथ हम हैं किसी भी राष्ट्रीय विपत्ति के समय हम जनता के साथ हैं और इसलिए महोदया, मैं यह कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार इसमें पूरी पारदर्शिता बरते और जनता के सामने पूरा एकाउन्ट रखे। धन्यवाद।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT : Madam Deputy Chairman, when the earthquake struck Gujarat, I was in my house. I felt as if the whole house was being jostled from this side to that side. It went on for 45 seconds. Nobody was in the House. Some persons knew it was an earthquake. This was for the first time an earthquake occurred in Ahmedabad. When everyone realised that it was an earthquake, they came out. Some people could not come out because they were staying in the seventh, eighth and ninth floors of multistoreyed flats. When they were trying to come out the whole structure of the building crumbled like a pack of cards. Hundreds of people were beneath the structure. Some of them were saved by the neighbours, fire brigade and other people. I agree with my friend, Mr Anantray Devshanker Dave that what is now required is resettlement of the people, they should be treated properly and think what is to be for them in the future. But the question is when it happened, what was the attitude of the Government? What was our Chief Minister doing? That is also very much relevant and very important thing. Madam, when the Chief Minister came to know about this incident, he was sitting in his office. He had no assessment of the situation. He did not know what has happened and where it has happened. He did not get feedback from any district. The journey from Ahmedabad to Bhuj by helicopter takes only one hour. The Government have aircraft and helicopters at their disposal. The Chief Minister could have ordered for a helicopter and flew to Bhuj to see for himself as to what has happened.

But, instead of seeing for himself personally, instead of knowing what was happening in Bhuj and other places, he sent a team of officials. Five officials were sent. That too after six hours! He took six hours to decide who should be sent and who would go! That took five hours. After five hours, the officials went there. In the meanwhile, in Ahmedabad, 179 high-rise buildings collapsed. They could not be vacated because there was no information from the Government as to what was happening.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair]

Mr. Vice-Chairman, Sir, it is said that the telecommunication system was not in order. That was only for 40 minutes. The telecommunication system was not in order for 40 minutes only. All telephones were working. Telephones to Bhuj also started working. Even if it was not working, they have got the police wireless. In Gandhinagar, there is the Army, there is the Air Force. They could have known what was happening through their wireless systems. Our hon. Chief Minister had not tried to know even through these sources as to what was happening in Gujarat. Meanwhile, 44 teams from outside started landing in Ahmedabad. Some of them started landing in Bhuj also. They came with their own equipment, with their own operation theatres, operation tables, chairs, milk and water, everything. They demanded nothing. But how to start the work? Where to start the work? There was nobody to lead them and guide them. That was the unfortunate system.

Mr. Vice-Chairman, my stress is that the Government could not assess the devastation caused by the earthquake. How big was the devastation, the Government had no idea. The Chief Minister was sitting in his chamber, sending persons there and trying to know what was happening. I will give an example, Sir. Mr. Vice-Chairman, when the Machhu dam burst...*(Interruption)*. Mr. Mehta, please do not try to defend them. Please take your seat. *(Interruption)*. Please listen.

श्री ललितभाई मेहता : आप तथ्यों को मरोड़ कर मत रखिये। ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपका समय आएगा।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: When the dam burst, the Chief Minister at that time, Mr. Babubhai Patel, did not send any deputation. He did not send a team of bureaucrats. The Chief Minister went there immediately. He went there himself. He declared that he would work from Machhu, he would work from Morbi; he would not go to Gandhinagar. He directed all super bureaucrats to come to Morbi and stay in Morbi. I had stayed in Morbi along with him. He said that his secretariat would work from there. And, all necessary orders were passed by him. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपको समय मिलेगा। आप कृपया बैठिये। आप भी अपनी बात रखियेगा। ...*(व्यवधान)*... उनको बोलने दीजिये।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. George Fernandes might have gone there. He went by helicopter and came back. He did not stay there. My whole stress is that our Chief Minister did not go there. He should have gone there when this sort of catastrophe took place. He should have taken the cue from Mr. Babubhai Patel. Mr. Patel went to the spot and stayed there till the whole thing was over.

Mr. Vice-Chairman, in five taluks, Kutch, Morbi, Rajkot, etc., there was heavy devastation. Even then what happened? Even after two days, the Government had no information about the devastation in Bhuj. But what is surprising is that our Chief Minister announced that there was likely to be a severe earthquake within 48 hours. This was published by newspapers.

So, people were scared. Those who were trying to go into their houses, on hearing this announcement, they also came out. They were sleeping in the open. After this announcement, they again came back and started sleeping in the open. Now, the whole joke is that the astrologer, who made an announcement like this along with the Chief Minister, was put behind bars under the Prevention of Anti-Social Activities Act. What has the Chief Minister done? He perhaps took the advice from the astrologer. He may be known to the Chief Minister, and on the basis of the announcement of the astrologer, the Chief Minister announced that the earthquake is going to come. The poor astrologer was put in the jail for this announcement. Now, if the Chief Minister speaks like this without knowing his responsibility, what will happen? People will be scared.

श्री ललितभाई मेहता : ...*(व्यवधान)*...उसके आधार पर चीफ मिनिस्टर ने यह कहा ...*(व्यवधान)*... उसका अनुभव हमने नहीं किया ...*(व्यवधान)*... अब दिल्ली में भी दो-तीन झटके आए हैं ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप अपनी बात कहिएगा ...*(व्यवधान)*... आपकी बात लिखी नहीं जाएगी ...*(व्यवधान)*... आपकी बात इस प्रकार से लिखी नहीं जाएगी ...*(व्यवधान)*... आपकी बात इस ढंग से नहीं लिखी जाएगी। आप कृपया अपने नम्बर पर बोलिएगा। जो आपको कहना हो कहिएगा। जो बात है वह सुनिए। दूसरे की भी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*... कृपया आसन ग्रहण करें ...*(व्यवधान)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: He had made this announcement and people were scared. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJU PARMAR: Why should the Chief Minister create a stir in the media? ...*(Interruptions)*...

श्री ललितभाई मेहता : जब अहमदभाई बोले किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, जब वे बोले तब नहीं किया ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया आसन ग्रहण करिए।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, a control room was set up. ...(Interruptions)... That control room was started in the Chief Minister's office. From this fact, you can imagine the magnitude of devastation. This has been published by the State Government of Gujarat. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मेहता जी, यह आप बड़ा गलत कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप उनको बोलन दीजिए।

श्री ललितभाई मेहता : वे केंसी बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जब आप बोलेंगे तब आप अपनी बात कहिएगा। यह कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। यह बात कोई असंसदीय नहीं है। आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Vice-Chairman, Sir, he is wasting my time. ...(Interruptions)... Whatever he wants to say, he can say so later on. Why is he getting up like this? The State Control Room was started in Chief Minister's office. There was no systematic monitoring going on, and only after five days, things became clear, and they started the necessary relief work. A number of trucks from other States came into Gujarat. I know that 150 trucks, loaded with materials, have come from Rajasthan. Trucks from other States have also come. It has also come from Maharashtra. Only then the whole thing of giving relief material to the people started and it was set in order. Then, the Prime Minister came. He was taken to certain places. I know that he has gone to various places and he has seen them. It may be late. From Ahmedabad, he was not able to see much excepting one civil hospital which was near to the annexe of the circuit house building. He saw that.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय भट्ट जी, आप अब संक्षेप में अपनी बात खत्म करें।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: No, Sir. I have so many things to say. Then, he said, it is "Rastriya Aapada". That was what he has said. The Chief Ministers of other States have declared, decided and demanded that the Government of India should declare this calamity as a national calamity. I would like to know from the Government in very clear terms as

to what are the terms and norms of a national calamity. He should clarify that. When 20,000 persons have died, when lakhs of buildings have been destroyed, when there is such a big devastation, I would like to know whether this can be termed as a national calamity or not. What will be the norms and terms of a national calamity. The Minister should explain as to what the position is as far as the Government is concerned. One suggestion which was made by Shri Dave is good. He has stated that a Gujarat Earthquake Management Authority should be constituted. I would go further and say that the Earthquake Disaster Management Authority should be formed so that the NGOs can be entrusted some work and good work may be done.

Otherwise, people are going to start an exodus rumpus because there are no facilities now. Yesterday, I saw on T.V. that a young man whose brother's body was lying buried went to the authorities and said, "Please send somebody." They said, "You are a young man. There is no person with us." The man tried to bury the body. He tried to take out the body of his own brother. He had to make pieces of the body. He took out the pieces of the body and burnt them. That was the position yesterday. That is the position even today. A new NGO should be entrusted with the work.

Sir, they are collecting funds in the name of Kutch devastation. May I remind this House that for Kargil Fund, they have taken Rs.24 crores? Out of Rs.24 crores, only Rs.20 crores are deposited in the bank; not sent to the Kargil Fund, not sent to the Ministry of Defence. Even today, the fund is lying there. Now, they are collecting funds! Sir, you will be surprised to know what the position today is. Forget about the general people's position. Forget about the common man's impression. Here is an impression of the Government servant when the Chief Minister is sitting. कर्मचारी महामंडल सेक्रेटरी, उपेन्द्र चौहान ने कहा कि कंट्रीब्यूशन देने में हमें कोई आब्जेक्शन नहीं है. "But we don't want to deposit in the fund of the Chief Minister!" This is what is said by the General Secretary of Employees Association of the Gujarat Secretariat. He says, "Whether proper use will be made of this fund or not, very likely, there will be corruption in the utilisation of the fund." This is what the Chief Minister's own people are saying! This is the position in Gujarat. Therefore, I submit that an authority like this should be organised and all parties should be taken into confidence. There should not be a monopoly of people who are sitting in the Sachivalaya. We also have to do something for the people of Gujarat. An authority is formed.

Good; no objection. But there should be representation of all parties, at least all parties which are in the State Assembly of Gujarat. That should be done.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय भट्ट जी, अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्मकुमार भट्ट : ठीक है, सर।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, I will conclude in one or two minutes. "One lakh buildings are to be built." How one lakh buildings will be built, let that be made clear to the people. "Some of them will be built before monsoon." In June, the monsoon will start. Instead of making announcements, concrete work should be done. That is the only requirement in the situation existing today. Our Army has really done a very good work. The entire people of Gujarat appreciate that. The only thing is that a lot of tents have come up, only in number. How those tents have been distributed, where those tents have been distributed, that should also be made clear.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : भट्ट जी, आप आसन ग्रहण करें।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: I want to make only one point. ...*(Interruptions)*... Only one point, so far as Ahmedabad is concerned. So many buildings are brought down by authorities after the earthquake, but there are some buildings which were to be brought down, but those buildings are now given protection by people who are sitting in the Sachivalaya. Sir, there is a building near the place I stay. It is known as the Anganwadi area. There, we were not allowed to go on that road for six or seven days. For seven days nobody was allowed to go on that road, saying that any minute this building would fall. The building's name is Shivalika. This has appeared in the Press. Then some pressure came from the Sachivalaya and it was said, "The builder and a very senior Minister in the Sachivalaya are partners. The building is in a partnership. There is a multiplex cinema on the Ashram Road. There also, they are partners. Therefore, the building will not be brought down. Some repairs will be made." ...*(Interruptions)*... This has appeared come in the Press, Patel Sahib. The High Court has interfered. The High Court has made a *suo motu* writ, taking cognizance of the reports in the newspapers; the matter is before the High Court, and the truth will come out.

Everyone, including yourself from Ahmedabad, knew what happened to the Shivalik building. All builders who have constructed this

type of buildings, irrespective of their political affiliation, should be treated on the same lines and the law should be allowed to take its own course. Thank you.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the devastating earthquake that took place in Gujarat and other parts of the country on the 26th of last month is the severest earthquake in the history of India.

As per the statement of the hon. Minister, more than 19,000 people died and about 1.67 lakh of people were injured. About 1.59 crore of people in 7,904 villages, that is, half of the population of Gujarat, have been affected by the earthquake. Lakhs of houses were destroyed and damaged. On behalf of our party, I convey our condolence, and extend our sympathies, to those who are affected and express our solidarity with the people of Gujarat in this hour of crisis.

Though the State administration could not respond, as was needed, the rescue operations by the Army, the Navy and the Air Force, and other organisations were highly appreciated. The Union Government acted promptly, by releasing a sum of Rs.500 crores on 30th January, 2001, and it took all the political parties into confidence at the meeting held on 3rd February, 2001.

An all-party National Committee on Disaster Management has been set up, not only to suggest short-term and long-term steps for relief and rehabilitation of the earthquake-affected Gujarat, but also to deliberate on the necessary institutional and legislative measures for evolving an effective and long-term strategy to deal with natural calamities.

The Union Government has also provided financial concessions and relaxation, such as exemption from customs duty, excise duty, income-tax, etc., on the contributions made towards relief.

Our country is proud of its humanitarian concerns and traditions. Almost all State Governments, institutions, organisations and individuals have come forward with contributions in cash and kind for relief and rehabilitation.

I feel proud of our Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu, who was the first to respond, and release a sum of Rs.5 crores, apart from 15 lorry-loads of rice, clothes, medicines, etc. Twelve police communication

experts and fifteen ham operators were also sent by our Chief Minister. The World Bank and many countries are also coming forward to help the Gujarat victims liberally.

Now, it is the bounden duty of the State Government and the Union Government to see that every rupee or article is utilised properly, with transparency. Not even an iota of an opportunity should be given to anybody for criticising and politicising this great tragedy.

The unprecedented earthquake in Gujarat has led me to an anguished questioning of the Government's ability to manage major disasters. Natural disasters such as earthquake, cyclones, floods, train accidents or landslides can occur despite all the precautions and early warnings. A high state of readiness is required to cope with the consequences. The management of such a disaster has been, and will remain, beyond the capability of the State Government machinery. Major disasters such as the earthquake in Gujarat and the cyclone in Orissa require major administrative, organisational, technical, logistic and infrastructural capability.

My humble suggestion to the Union Government is to consider the creation of a special organisation to work out the reconstruction process systematically over a few years.

Both the Union and the State Governments should take steps that have far-reaching effects. Experts in seismology should draw up a code to ensure quake resistance and create awareness about the need for constructing buildings that can withstand earthquakes or tremors.

In the recent past, earthquakes or tremors have been felt in Indonesia, El Salvador, Turkey, and in our own country, in Latur, where a huge number of lives and properties were lost. Hence, it is the concern of many countries of the world. I feel that India should take the lead in hosting an international conference to initiate research in regard to earthquakes as to how we can predict them.

The seismic zones have been categorised on the basis of the survey done in 1893. I urge upon the Union Government to undertake a resurvey and recategorize the zones. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (रमा शंकर कौशिक) : श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी। अनुपस्थित। श्री ललितभाई मेहता।

श्री ललितभाई मेहता : उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्षों के दौरान जो बातें यहां पर रखी गईं, मैं समझता हूँ कि जब भी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं और उन प्राकृतिक विपदाओं के साथ-साथ बचाव के, राहत के और पुनर्वास के जो काम होते हैं, उनमें राजनीतिक आक्षेपबाजी होती रहती है। वैसी ही कुछ आक्षेपबाजी आज यहां पर भी हुई। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सीधा-साधा कहना यह है, ब्रह्म कुमार भाई ने बताया कि मुख्य मंत्री जी गांधी नगर में अपने आफिस में थे। आप रिकार्ड देख लीजिए, 9:20 मिनट पर पुलिस कंट्रोल रूम, अहमदाबाद में मुख्य मंत्री जी आ गए। ब्रह्म कुमार भाई ने यह बताया कि बाबूभाई जसभाई पटेल मोरबी में जाकर बैठे, मैं भी उस वक्त मोरबी में था, लेकिन पांच दिन तक पूरे कच्छ का इलाका कम्युनिकेशन की फेसिलिटी न होने के कारण सारे गुजरात और देश से कटा हुआ था और मोरबी एक सोलिटरी प्लेस था, जहां पर यह प्राकृतिक विपदा हुई और पूरे गुजरात के 21 जिले, 9000 से ज्यादा गांव और गुजरात के 180 जो तालुके हैं, इन तालुकों की प्लेसिस में अगर कुछ संकलन करना चाहिए, राहत सामग्री भेजने की बात ... (व्यवधान)...

SHRI BRATIN SENGUPTA: We went there with Rs. 5 crores to meet the Chief Minister. But we could not meet him. He refused to meet us. ... (Interruptions)...

श्री ललितभाई मेहता : मैं कह सकता हूँ कि उसी दिन 4:00 बजे केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री, माननीय आडवाणी जी अहमदाबाद में पहुंच गए थे। उसी दिन शाम को केन्द्रीय सरकार की तत्कालीन कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई थी और 24,000 जवानों को यहां पर भेजने की व्यवस्था तत्काल वहां पर हो गई थी। मलवा हटाने के लिए जितनी भी साधन-सामग्री, जहां से भी प्राप्त हो सके, वह सब भेजने की भी व्यवस्था उसी दिन हो गई। जिस तीव्र गति से तंत्र को काम करना चाहिए था, उस बारे में सब निर्णय उसी दिन लिए जा रहे थे, लिए गए थे और राहत सामग्री पहुंचाने की, बचाव कार्य करने की व्यवस्था सब उसी दिन हो रही थी। एक बात यह बताई गई कि मकान के घटिया मानदंडों के कारण यह हुआ और इसमें सरकारी पक्ष के लोग शामिल हैं, सुरेन्द्र पटेल का नाम लेकर श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने बताया। मैं यह बताना चाहूंगा, मेरे पास यह ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि बिल्डरों के बारे में 304 कल्पेबल होमिसाइड, 120 और 420 की आई पी सी की धाराएं लगाकर के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ... (व्यवधान)...

महोदय, गुजरात में आया यह भूकम्प पिछले 110 सालों में दुनियाभर में जो 20 भूकम्प आए, विशालता और विकरालता की दृष्टि से यह विश्व में आए सभी भूकम्पों में सर्वाधिक विनाशकारी था और इसी कारण जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ, उस परिस्थिति में सरकार के साथ-साथ अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने, अनेक राज्यों की सरकारों ने, केन्द्रीय सरकार ने तुरन्त जो कदम उठाए, उसके कारण सिर्फ तीन दिन में परिस्थिति सामान्य होती दिखाई दी। अब देखिए कि कच्छ का पूरा जिला जहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि, पुराने राजे-महाराजे, सम्पत्ति वाले अनेक महाशय, जिनकी सब सम्पत्ति नष्ट हो गई थी और सब भूमिगत हो गया था, ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने, गुजरात के सामने यह समस्या थी कि बचाव के काम पहले से शुरू कर दिए जाएं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लोग कहते हैं कि राहत दत्त 8 घंटे तक नहीं पहुंचे, 10 घंटे तक नहीं पहुंचे, यह बात सही हो सकती है लेकिन एक ही दिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने कच्छ जिले में 1420 लोगों को मलबे से बाहर निकाला, यह बात कोई नहीं

कहेगा। दो दिनों में इन स्वयंसेवकों ने 1500 भाइयों और बहनों का अंतिम संस्कार किया, यह बात भी कोई नहीं कहेगा। महोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके साथ जुड़े हुए अन्य संगठनों के 25,000 कार्यकर्ताओं ने 26 तारीख से लेकर आज के दिन तक राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह बात यहां पर नहीं कही जा रही है। देखिए, उस दिन गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल के लोग जिला मुख्यालय में थे। जिनको इस कार्य का जिम्मा दिया गया है, श्री सुरेश भाई मेहता, जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के, वे खुद वहां पर मौजूद थे और इनका बराबर केशूभाई के साथ संपर्क बना हुआ था और वे बचाव और राहत कार्यों में कितने सक्षम रहे, इसका अनुभव पूरे कच्छ के लोगों को हुआ। मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा कि कई पत्रकार मित्र न, जिनका ज्यादातर नामधेरी मित्र है, उन्होंने क्या कहा लेकिन ऐशियन एज की एक महिला पत्रकार दीपल त्रिवेदी न कहा है कि 100-100 घंटे बाद भी मलबे से आदमियों को जिंदा निकालने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे दबे आदमियों की दांते टांगें काटकर, ऑपरेशन करवाकर उनको जिंदा बाहर निकाला गया। वैसे दीपल त्रिवेदी स्वयं कहती हैं कि मैं अपने पूरे जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सख्त आलोचक रही हूँ, कभी भी इनके लिए मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था लेकिन आज अगर मैं पत्रकार का धर्म निभा सकती हूँ तो इसका सारा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को है। वे कहती हैं कि मेरे ऊपर जो आपदा आई थी, उसके 2 घंटे के भीतर इन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया और वहां जो राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए थी, उसे इन लोगों ने पहुंचाया है।

महोदय, अहमदाबाद के क्रिश्चियन मिशनरी चर्च के फादर प्रकाश ने कहा कि हमारी पुलिस, हमारी प्रैस, गुजरात की सरकार, गुजरात का प्रशासनिक तंत्र, इन सबने परिस्थिति को सामान्य बनाने में इतना परिश्रम किया है कि हम एक भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। महोदय, दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है, उसमें भी कहा गया है कि गुजरात में केशूभाई पटेल की सरकार ने जिस द्रुत गति से परिस्थिति का आकलन किया और जिस गति से राहत और बचाव कार्य शुरू किया, उसे हमें कम नहीं आकलना चाहिए।

महोदय, स्विटजरलैंड के एक पत्रकार मित्र जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि विदेशों से वेशक हमें आपातकालीन सहायता-सामग्री मिली होगी लेकिन यहां पर जिस निःस्वार्थ भाव से, जिस कर्तव्यनिष्ठा से, जिस एकता का परिचय देकर सारे प्रशासनिक तंत्र ने, सरकार ने और स्वयंसेवी संस्थाओं और पूरे देश से आए हुए लोगों ने काम किया है, हम विदेशों में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां जिनका कच्छ जिले का चार्ज दिया गया है, वहां पर जिसका आज चार्ज दिया गया है कच्छ जिले के कलेक्टर अनिल मुखी यह कहते थे कि ऐसी विपदा में लोग पूरी तरह से दूट जाते हैं, स्थान छोड़ कर भाग जाते हैं, सब ओर अव्यवस्था फैल जाती है। लेकिन सरकार की व्यवस्था के कारण, समाज के सहयोग के कारण आज पूरे कच्छ में से माइग्रेशन नहीं हुआ, लोग वहीं पर हैं और बचाव तथा राहत सामग्री ठीक तरह से पहुंच पाई है। एल. मान सिंह जो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको वहां का चार्ज दिया गया है, उन्होंने कहा कि गुजरातीयो की संकल्प शक्ति बहुत है जिसके बल पर पुरुषार्थ और सहयोग से गुजराती लोग फिर से खड़े हो जाएंगे और इनको जो सहायता चाहिए थी वह सहायता समय पर दिलवाने में हम अधिकारी लोग सफल रहे हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। जिन्होंने यह बात कही वह बात मैंने आपको बताई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : महता जी, आपका समय पूरा हो रहा है, कृपया समाप्त करें।

श्री ललितभाई मेहता : मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

गुजरात में भूकम्प के कारण सामाजिक और मानवीय नुकसान तो हुआ लेकिन आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है। 21882 करोड़ रुपये की नुकसानी हुई ऐसा माननीय मंत्री जी ने अपने निवेदन में बताया है। फिर भी आज गुजरात की जो आर्थिक स्थिति है, गुजरात वैसे उद्यमशील राज्य है। देश में औद्योगिकीकरण की दृष्टि से देखें तो गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर औद्योगिकीकरण हुआ है। 1990 से लेकर 2000 के साल तक इन 10 सालों में हमारी विकास की दर 8 प्रतिशत से भी ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन 1990 के साल तक यह देखें कि 7.3 प्रतिशत आर्थिक विकास देश में हुआ था और यही कारण है कि देश में जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसमें 11 प्रतिशत हिस्सा गुजरात अपना दे रहा है। हमारे लिए संतोष की बात है कि आज भी इतनी बड़ी त्रासदी होते हुए भी गुजरात में 326 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में है। एक लाख अड़सठ हजार दो सौ करोड़ रुपये का विनिवेश इसमें हुआ है। उसमें से एक भी उद्योगपति ऐसा नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि हम गुजरात में अव्यवस्था के कारण या सरकारी व्यवस्था न होने के कारण इस त्रासदी के कारण हम अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे और आगे नहीं चलाएंगे। देश में 1990 से लेकर 2000 तक जो कुल विनिवेश हुआ तीन लाख चारह हजार इक्कीस करोड़ रुपये का उसमें से गुजरात में 75127 करोड़ का विनिवेश हुआ। इस साल 1999-2000 के एक साल में 31960 करोड़ रुपये का विनिवेश पूरे देश में जो होने जा रहा है उसमें से 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा 3195 करोड़ रुपये का हिस्सा गुजरात का है। गुजरात में पोर्ट, एल.एन.जी. टर्मिनल और पावर सेक्टर इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है पोर्ट में 20956 करोड़ रुपये का, एल.एन.जी. टर्मिनल में 13810 करोड़ रुपये का और पावर प्रोजेक्ट में जो विनिवेश हो रहा है उसमें से एक भी उद्योगपति ने यह नहीं कहा कि अब हम गुजरात छोड़ कर चले जाएंगे। मेरे लिए यह बातें बहुत महत्व रखती हैं क्योंकि आज गुजरात जो आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था उसमें थोड़ी रुकावट आई है। लेकिन फिर भी हमारे एक वरिष्ठ मित्र -सांसद श्री दवे ने बताया कि हम चाहते हैं कि 13500 करोड़ रुपये की राशि गुजरात के लिए चाहिए, यह मांग हमने केन्द्र की सरकार से की है। केन्द्र की सरकार इस बारे में जरूर सोचे। जो बजट आ रहा है दो दिन के बाद, उस बजट में कच्छ के लिए कुछ विशेष पैकेज की बात कही गई है वह बिल्कुल सही है। लेकिन गुजरात के बाकी सभी विस्तारों के लिए भी कोई विशेष पैकेज की योजना बने।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय महता जी, कृपया आप समाप्त करें।

श्री ललितभाई मेहता : गुजरात के लोगों का मदद मिले यह बात हमें देखनी होगी। उपसभाध्यक्ष जी, भूकम्प ने यह गाना कर दिया है कि बौद्धिकता से अधिक संवेदना होती है। समाज में आत्मीयता और संवेदना का भाव जगाना जो आज पूरे देश में भाव हमारे सामने आया है, तो यह समाज में आत्मीयता और संवेदना का भाव जगाना यही वास्तविक राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज के प्रति आत्मीयता और संवेदनशीलता इसका अधिष्ठान जो रहता है वह आध्यात्मिक रहता है। इसका परिणाम व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में इस त्रासदी के बाद हमको देखने को मिला है। इसको याद करने हुए हम इस प्राकृतिक विपदा से बाहर निकलने के लिए सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

डा. कुमकुम राय (बिहार) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। 26 जनवरी, 2001 को जब सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो 8.46 मिनट पर रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता वाला एक गंभीर भूकम्प आया जिसका केन्द्र विन्दु भुज के 20 कि.मी. उत्तर पूर्व में स्थित था। इसका अनुभव देश के विभिन्न भागों में भी किया गया किन्तु गुजरात बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

गुजरात की गिनती भारत के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती थी। देश के समूचे क्षेत्रफल का मात्र छह प्रतिशत और आबादी का पांच प्रतिशत हिस्सा रखने वाला गुजरात भारत की पूरी अर्थ-व्यवस्था में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान किया करता है। लेकिन भूकम्प ने गुजरात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके 21 जिले, 182 तालुके और 7904 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब डेढ़ करोड़ की आबादी इससे प्रभावित हुई है। इसमें मरने वालों की संख्या पर विवाद है। हमारे रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज साहब जब वहां गए तो उन्होंने कहा था कि करीब एक लाख लोग इसमें मरे हैं, लेकिन कृषि भवन की जो सरकारी विज्ञप्ति निकली है उसके अनुसार मृतकों की संख्या 17549 है और घायलों की संख्या 166836 है। वहां पर प्रशासन की चुस्ती का आलम यह था कि कच्छ के कलेक्टर ने 17 घंटे बाद गुजरात सरकार को सूचित किया कि कच्छ जिले की बजर जमीन मलबे और शवों से पट गई है। स्विस् राहत दल 27 जनवरी की दोपहर अहमदाबाद पहुंच गया किन्तु हवाई अड्डे से उसे तुरन्त बाहर निकालने के बजाय तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में ही उसके दो घंटे बर्बाद हुए, जबकि भूकम्प के बाद के 48 घंटों को लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। केवल देरी ही नहीं हुई बचाव और राहत कार्य भी यांत्रिक रवैए के कारण बाधित हुआ। भूकम्प के लगभग 36 घंटों के बाद तक सरकार मलबे को हटाने और वहां फंसे जीवित लोगों को निकालने के लिए क्रेन और मिट्टी हटाने वाली बड़ी मशीनें जुटाने में लगी रही। यह स्थिति देश के सबसे धनी एवं विकसित राज्य की थी।

कच्छ का भुज या अंजार इलाका ही ऐसा नहीं था जहां सरकार सीधे संसाधन नहीं जुटा पाई। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के एकदम पड़ोस में होने के बावजूद गांधीधाम के निवासियों को मलबा हटाने वाली भारी मशीनों का अंतहीन इंतजार करना पड़ा।

अहमदाबाद की ही बात करें तो सरकार तीन दिन तक क्रेन और मिट्टी हटाने वाली मशीनों को लाने के लिए जूझती रही। मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल को दूरदर्शन पर गैस कटर के लिए अपील करने में 48 घंटे लग गए। संकट पर काबू पाने का एक बुनियादी सिद्धान्त यह है कि सूचनाओं की आवाजाही तेज हो। इसलिए पहला काम संचार लाइनों को खोलने का होना चाहिए था। सरकार न केवल शीघ्र संवाद कायम करने में विफल रही बल्कि उसने प्रायः गलत संदेश दिए। भूकम्प के एक दिन बाद पत्रकारों से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने रहस्योद्घाटन किया कि मलबे में अब भी सवा लाख लोग दबे हुए हैं। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया। उनके बयान से आया तूफान थमा भी नहीं था कि उनकी एक और घोषणा ने दूसरा तूफान ला दिया। उन्होंने कह दिया कि भूकम्प और 48 घंटे तक गुजरात को झकझोरेगा और लोग असुरक्षित इमारतों से दूर रहें। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों तरफ आतंक ही आतंक फैल गया।

सरकार को सक्रिय होने में तीन दिन लगे। देश की सेना तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, विदेशी संस्थाओं एवं कुछ औद्योगिक घरानों तथा कुछ धार्मिक संस्थाओं ने गुजरात में राहत एवं बचाव कार्य में प्रशंसनीय कार्य किया है। विभिन्न राज्यों ने भी मदद पहुंचाई है। हमारे बिहार की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने भी पांच करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई है। दरअसल भूकम्प खुद किसी की जान नहीं लेता, यह काम तो दोषपूर्ण ढंग से बनी इमारतें करती हैं। जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स थीं, इमारतें थीं, वे अधिकांश जर्मीदोज हुईं।

गुजरात त्रासदी में नुकसान का मुख्य कारण यह था कि भवन निर्माण में भूकम्प विरोधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया जो कि 1970 से ही लागू है। यदि इसका पालन किया गया होता तो इतनी जन-धन की क्षति नहीं हुई होती। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इन दिशा निर्देशों को निर्माण कानूनों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए क्योंकि गुजरात में हुई विनाशलीला का प्रभाव समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा है। अतः युद्धस्तर पर गुजरात में पुनर्वास का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। जिसके लिए काफी संसाधनों की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी ने पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है और दुनिया भर से गुजरात को मदद देने की घोषणा हो रही है, वहां से मदद आ रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में देश के सार्वजनिक और निजी संस्थान, स्वयं सेवी संगठन और लोग भी गुजरात के लिए काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल मदद के उचित प्रबंधन का है। जो मौजूदा सरकार से संभव नहीं दिखाई पड़ता। अतः अपने राजनैतिक नफा नुकसान की गणना से अलग प्रधान मंत्री को चाहिए कि वे या तो वहां की कमान किसी और को सौंपे या मौजूदा नेतृत्व से ही अधिक सक्रिय होने का आग्रह करें। कायदे से गुजरात में त्रिस्तरीय कार्यवाही की जरूरत है। एक तो भूकम्प पीड़ितों को तात्कालिक राहत पहुंचाने का प्रश्न है - यानी जो घायल और बीमार है, उन्हें चिकित्सा मुहैया कराई जाए, लोगों को भूखमरी, ठंड और लूटमार से बचाने के उपाय किए जाएं। दूसरी ओर ज्यादा बड़ी चुनौती उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास की है। इस सिलसिले में सबसे जरूरी चीज पुनर्वास के खर्च का सही आकलन और प्रबंधन है। राहत सही हाथों तक पहुंचे और उसका सही इस्तेमाल हो, यह भी ध्यान रखने की बात है। उजड़े हुए लोगों के बड़े हिस्से के पास अपने दावे की पुष्टि में कागजात नहीं भी हो सकते हैं। प्राणी जा शुद्ध स्थायी किरम की नौकरियों में नहीं हैं या फिर अपनी सम्पत्ति से जुड़े जिनके कागज भूकम्प में नष्ट हो गये हैं, न वे मदद से वंचित हों और न उनकी आड़ में गलत लोग पैसे बनाने का पधा शुरू कर पाएं। यह भी रुचित होगा कि यह पता लगाया जाए कि किन कारणों से गुजरात में भूकम्प प्रतिरोधी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सका। इसके लिए जो भी उत्तरदायी हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। स्विस् राहत टीम में आए प्रशिक्षित कुत्तों ने भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। इस प्रकार के प्रशिक्षित कुत्तों की टीम हमारे यहां भी बनायी जाए क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति जो मलबे में दबे रह जाते हैं, उनकी पहचान कर सूचना देते हैं। इन सब उपायों के साथ साथ शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर भूकम्प विशेषज्ञों की एक स्थायी आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाए जिसमें सभी दलों के नेता भी शामिल हों। इसके अलावा गुजरात में आय कर, कस्टम ड्यूटी आदि में छूट के भी उपाय किए जाएं। राहत और बचाव जो हुआ सो हुआ, किन्तु भुज के क्षेत्रों के विषय में जो सुनने में आ रहा है कि वहां के कुछ इलाकों को ज्यों का त्यों रखा जाएगा और उसे पर्यटक स्थलों के रूप में रखा जाएगा ताकि आगे आने वाले दिनों में पर्यटक वहां आकर उस विनाश लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। इस प्रकार मौत की इस त्रासदी के व्यापार को रोकने के प्रयास किए जाएं। अंत में मैं एक सलाह और देना चाहती हूँ कि गुजरात के नुकसान की भरपाई आसकर पर दो प्रतिशत अधिभार

लगाकर नहीं हो सकेगी बल्कि इसके लिए नौकरशाही पर होने वाले खर्च घटाने और सरकारी फिजूलखर्ची रोकने, अनावश्यक विदेश यात्रा रोकने जैसे उपाय भी सरकार को करने चाहिए। बीच में जो इस प्रकार के भेदभाव की शिकायतें मिल रही हैं, जैसे गुजरात के कमजोर वर्ग के जो इलाके हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां अभी तक राहत और पुनर्वास के कार्य शुरू नहीं हुए हैं। इसका एक उदाहरण राज्यपाल महोदय की उस यात्रा में मिला जब वे बड़मार में भूकंप पीड़ितों के बीच जा रहे थे क्योंकि उस समय तक उनके बीच राहत का कोई कार्य नहीं किया गया था। लेकिन जिस दिन राज्यपाल महोदय वहां जाने वाले थे, उस दिन सुबह सुबह उन लोगों को कंबल बांटे गये। नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल महोदय की गाड़ी जब उन लोगों के बीच पहुंची तो उन लोगों ने अपने कंबल उनकी गाड़ी पर फेंक दिये और अपना आक्रोश जाहिर किया। नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल महोदय वहीं से वापिस लौट गये। इस प्रकार ऊंच नीच और गरीब अमीर का भेदभाव न करते हुए अनेक ऐसी जा शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। पिछले दिनों अखबार में भी निकला कि जापान से जो अच्छे टैंट आए थे, वे किसी बड़े व्यक्ति के पेट्रोल पंप पर लगे देखे गये, उनकी कोठियों के प्रांगण में देखे गये। इस प्रकार की शिकायतें मन को दुखी करती हैं क्योंकि इस मानवीय त्रासदी में सारा देश ही नहीं, पूरा विश्व शामिल है इसलिए सारे विश्व की राहत जो वहां पहुंचाई जा रही है, उसको उचित हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने में सरकार को अपनी चेष्टा करनी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI KA. RA. SUBBIAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, with deep sorrow and grief, on my own behalf and on behalf of the six crore people of Tamil Nadu, I extend my heartfelt condolences on the demise of so many people in Gujarat. I also feel sorry for those people who have been affected by this earthquake and for the loss of property there. I also pay my homage to the memory of those people who have died in this unprecedented earthquake. Property worth several crore of rupees has been damaged. Of course, now, in order to overcome this suffering which has been caused due to the onslaught of this natural calamity the National Committee on Disaster Management consisting of all parties, has been set up. The relief work is being done on a war-footing. As far as our State is concerned, not only are we extending our heartfelt condolences on behalf of our Party, but Dr. Kalignar had immediately announced an assistance of Rs. five crores, towards the Gujarat Government's Relief Fund. Several voluntary organisations and medical teams were sent to Gujarat with medicines and other materials. Our Government not only gave an assistance of Rs. five crores but sent other material also. Several other voluntary organisations are also collecting funds for the people of Gujarat. People from all walks of life are contributing money to the Chief Minister's fund. We could see from every nook and corner of the country and all over the world that people have come forward to help. They are contributing to the maximum extent. Sir, this House is fully aware that this type of calamity cannot be predicted.

4.00 P.M.

But we know that a severe drought or floods or cyclone or earthquake always affect one part of the country or the other. ...*(Interruptions)*... The recent earthquake reminds us that there was no sufficient fund kept apart for this purpose. Therefore, I would like to call upon the Government to create a national impression so as to facilitate quicker delivery of funds to the affected States or the people. I also demand that fund should be identified for studying continuous seismic movement zones in India and on-line data should be collected from the rest of the world and should be taken into account for research and development in the affected areas. With these words, I conclude. Thank you.

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (झारखंड) :** सदरे मोहतरम, गुजरात के हादसे पर हाऊस में आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथियों ने जो कुदरती आफत गुजरात में आई उस पर अपने गहरे गमो-अलम का इजहार किया है। मैं भी अपने तमाम साथियों के साथ गुजरात की सर जमीन पर आई हुई कुदरती आफत के नतीजे में हलाक होने वाले लोगों के खानदानों के साथ इजहारे ताज्जियत करते हुए उनके गम में अपने आपको शरीक करार देता हूँ। सदर साहब, जब कोई आफत आती है तो वह जात, बिरादरी, दीन, धर्म का मुंह देख कर के नहीं आती और उसमें हर तरह के लोग बदकिस्मती से पीसे जाते हैं। उस आफत का मुकाबला करने के लिए जब राहत-रसानी का काम होता है उस काम में भी हमें कुदरत के फैसलों से सबक लेना चाहिये। जिस तरह तूफान आता है वह कोई अपना बैगाना नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, अच्छा बुरा नहीं देखता, सारे के सारे लोग उस तूफान की नजर हो जाते हैं। ऐसे ही तूफान के हिचकोले से इन्सानियत की किशती को साहिल पर लाने के लिए हम लोगों को जद्दोजहद करनी चाहिये, हमें लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहिये, जाति बिरादरी के पैमाने से इन्सानियत के सुलगते हुए मसायल को न माप कर उसे समता, इन्साफ और ह्यूमेन राइट्स के जजबात को सामने रख कर अपनी खिदमात पेश करनी चाहिये। गुजरात की सरजमी पर बड़ी भयानक आफत आई है, अल्फाज के जामे में उस आफत, उस मुसीबत और उस पीड़ा को समाया नहीं जा सकता। गुजरात में जिन लोगों ने वह आफत देखी है वही लोग ज्यादातर इस बात को महसूस कर सकते हैं। उन परेशानहाल लोगों पर क्या गुजरी है सच्चाई तो यह है कि जैसे कि मेरे साथी ने बतलाया कि उनकी हालत को देखने के बाद अगर हस्सास दिल हो तो एक एक घर पर एक एक किताब लिखी जा सकती है मुसीबतों की ऐसी जबरदस्त कहानियाँ जन्म ले चुकी हैं जिन पर मरहमेशफा रखते हुए भी बहुत सारा वक्त लग जाएगा। जहाँ जहाँ से जिन जिन मुल्कों से हमारे भाइयों पर टूटी हुई आफत को खत्म करने के लिए और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इमदाद आई है हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम अपने हाऊस से उन मुमालिक का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमारी इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दे कर बैनलअक्वामी इन्सानी रिश्तों का गहरा नक्श हमारे ऊपर छोड़ा है। मोहतरम् अखबारों में तो बहुत कुछ आया है। मैं कोई ऐसी बात कहने से गुरेज करना चाहता

*Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

हूँ जो इस आपस में तलखी का मसला पैदा करे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मसायल को खुदा के लिए सिर्फ नजरे हमदर्दी के आइने में देखा जाना चाहिये। क्यासअराइयाँ बेकार हैं अब मरने वालों पर। "शिकन बिरतर की कहती है कि दम निकला है मुश्किल से"। गुजरात की सरजमीं के लोग बड़े हौसलामंद लोग हैं। गुजरात के हमारे भाई बहुत ही जाबाज लोग हैं, खुदार लोग हैं, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ गुजरात के भाइयों को जब उनके पास रिलीफ के सामान जाते होंगे किस मन से वह रिलीफ का सामान ले रहे होंगे किस मन से लोगों का दिया हुआ दाना-पानी खा रहे होंगे। मैं गुजरातियों की नफसियात से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ बहुत करीब से गुजरात के जियाले भाइयों को देखने का मुझे मौका मिला है। जो हाथ हमेशा देने की आदत रखते रहे आज वह हाथ लेने के वक्त पर अपने दिलो दिमाग में कौन सी कसक महसूस कर रहे होंगे हर उस सखीदाता के दिल में वह बात पैदा होती है जो हमेशा देना जानते हैं लेना नहीं जानते। गुजरात के भाइयों का यह बहुत बड़ा कमाल है वह हमेशा देना जानते हैं लेना नहीं जानते। उनका हाथ हमेशा ऊपर रहा है, कभी उनका हाथ नीचे नहीं रहा है। आज भी मैं यह कहना चाहूँगा कि वहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे गुजराती आबोहवा में अपनी खुदारी के माहोल में रहते हैं, वह भिखमंगई के शीशमहल में रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए उनके पास जब हमारी इमदाद जाए तो उनकी खुदारी को भी कहीं से टेस नहीं लगनी चाहिये उनकी इज्जतेनफस का टेस नहीं लगनी चाहिये। बड़ा ही प्यारा सूबा है हिन्दुस्तान की सरजमीं पर अपना एक गहरा नक्श लांगों के दिलोदिमाग में लोगों की मदद करने की बुनियाद पर उस सूबे ने छोड़ा है। आज अगर गुजरात मुसीबत में आया, कुदरत ने गुजरात की मुसीबत में भी अजीमोशान अजर दिया है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर हमदर्दी कम लोगों और कम इलाकों के लिए पैदा हुई होगी जितनी बड़ी हमदर्दी इंटरनेशनल तौर पर हमारे गुजरात के भाइयों के लिए खुदा ने पैदा कर दी है। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि वहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें हम एक दूसरे पर टिप्पणी करके क्या करेंगे। काम जहाँ होता है वहाँ अच्छा भी काम होता है, बुरा भी काम होता है। मगर जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के मामले में बहुत ज्यादा चौकस रहना होगा। वहाँ जो सरकार है, मैं उस सरकार पर ब्लेम तो नहीं लगाऊँगा कि सरकार मुर्दा हड्डियों पर सियासत करेगी, मगर कुछ लोग सरकार की आड में अगर मुर्दा हड्डियों पर सियासत कर रहे हों तो सरकार को चाहिए कि सरकार चौकस होकर बदनामी से बचने के लिए नेकनामी का रास्ता अपनाए और ऐसे बेईमानों का कड़ी से कड़ी सजा दे जो धर्म के नाम पर, जाति, बिरादरी के नाम पर ह्यूमन हमदर्दी खत्म करने की साजिश करते हैं। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबतों में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काशिश करते हैं। ऐसे बेईमानों पर भी सख्त नजर रखनी चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहूँगा। यह बात भूझे यह कहनी है कि इस जलजले में जो बिल्डिंगें तहस-नहस हुईं, उनमें भी यह बात आ रही है कि बिल्डरो को पकड़ा जाएगा और बिल्डरो में जैसी धोखेबाजी की है उन बिल्डरो को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी गुजारिश यह है कि जो भी बिल्डिंगें बनायी जाएं उन बिल्डिंगों का एक आलातरीन मेयार जरूर कायम किया जाए और ऐसा सख्त-तरीन कानून बनाया जाए कि अगर लोग बिल्डिंगों को बनाने में इन्सानो की जान लेने के दरमएआजार हों तो ऐसे लोगों को भी दफा 302 से कम की सजा तजवीज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि एक आदमी की जान बचाने के लिए तो हम दुनिया भर का डिफेंस करते हैं मगर एक आदमी अपनी धोखेबाजी और गलत मदीरियत के जरिए अगर हजारों आदमियों की

मौत का सामान करता है तो मेरा ख्याल यह है कि ऐसे आदमी को भी इस जिन्दा समाज में जिन्दा रहने का कोई हक नहीं मिलना चाहिए।

इसी तरह से दुनिया के जितने भी नुमातिक ने हमें अपनी अपनी सहानुभूति भेजी, हमने बड़ी फराकदिली के साथ उनकी सहानुभूति को कबूल किया। मुझे एक खबर पढ़ने को मिली थी। मैं उसे भी आपस में कट्रोवर्सी का शिकार नहीं बनने दूंगा। सिर्फ अपने भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि सच्चे दिल से उस खबर पर भी नजर रखनी चाहिए। पोप पाल जी ने भी हमारे यहां गुजरात के भाइयों की मदद करने का एलान किया था। उस पर अखबारों में खबर आई कि कुछ लोगों ने यह कहा कि पोप पाल जी मदद देंगे तो वह मदद नहीं ली जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों से हम परहज करना चाहिए। मुसीबत ही के वक्त दुश्मन भी दोस्त होते हैं। पोप पाल कोई हमारे दुश्मन नहीं है ... (व्यवधान) ... मैं वही कह रहा हूँ। इन्सानियत की खिदमत करने के लिए कोई भी तो मुसीबत के वक्त सब सामने आ जाते हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इस आसमानी आफत के नतीजे में दूरियां कम हुईं, आपस की रजिशें खत्म हुईं। लोग जो नदी के इस किनारे और उस किनारे अपने आपको महसूस कर रहे थे, एक मोहब्बत का पुल बनाकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। खुदा करे हम इसी तरह सारी बातों को मुल्क में पैदा करके एक इन्सानी हमदर्दी के नाते सारे हिंदुस्तानियों को एक रंग, एक ढंग, एक समाज और इन्सानियत के आफाक पर मुस्कुराते धांद की धांदनी की तरह दुनिया के सामने पेश करें जिससे दुनिया को टडक मिल सके।

गुजरात के उन तमाम मुसीबतजदगान भाइयों के लिए मैं एक मरतबा फिर अपनी तरह से इजहारे ताजियत पेश करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पाजिटिव अगर गुजरात के लोगों को हिमायत का हाथ बढ़ाकर दे दिया गया तो गुजरात एक बहुत खुदार सूबा है, गुजरात सारी दुनिया में अपनी खिदमात का एक मकाम रखता है, एक हिस्ट्री रखता है, कोई वजह नहीं कि गुजरात अपने पैरों पर न खड़ा हो। गुजरात के लोगों में बेपनाह हौसला है। वे खूब अच्छी तरह से जीना जानते हैं। वे जर्जों को सोना बनाना जानते हैं। वे मिट्टी से जिंदगी पैदा करना जानते हैं। इसलिए मैं हुकूमत से यह मतालबा करता हूँ कि हुकूमत उनकी पुश्त पर इतनी मजबूती के साथ हाथ रखे कि उनके दामन पर जो धब्बा पड़ा हुआ है और उनकी जिंदगी पर जो गुबार पड़ा हुआ है, प्यार मोहब्बत के हाथ से अगर उसे झटक दिया जाए तो गुजरात का चेहरा फिर निखरकर सामने आ जाएगा। गुजरात मदद लेने में यकीन नहीं रखता है। गुजरात मदद देने में यकीन रखता है। इसलिए गुजरात की मदद इस तरह से की जाए कि गुजरात कल फिर सारी दुनिया की मदद करने के काबिल हो सके। थैंक्यू, शुक्रिया।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी को यह भूकंप आया और उसके 18 दिन बाद मुझे उस इलाके में जाने का मौका मिला। भूकंप ने कितनी तबाही ढहाई है इसको मैंने देखा। 18 रोज बाद भी जो मैंने देखा उससे लगा कि किस तरह से लोगो ने इसे बर्दाश्त कर लिया। सरला जी ने ठीक ही कहा और इस जिजीविषा की बात उन्होंने की। मैंने देखा कि अंजार में एक 75 वर्ष का बूढ़ा, जहां मंदिर-मस्जिद की दीवाल गिर कर एक-दूसरे से सट गई थी उसी की बगल में वह 18 रोज के बाद भी मलबा उठा रहा था। मैंने पूछा कि इसमें आप क्या खोज रहे हो। उसने कहा कि स्टूल खोज रहा हूँ। स्टूल का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने खुद कुदाल उठाई और मलबे के बड़े टुकड़े को उठा कर उसके छोटे से स्टूल को

निकाल लिया। तब उसने कहा कि इसके नीचे मेरा एक टिन भी है। मैंने पूछा कि उसमें क्या है। उसने कहा कि मेरा सामान है। उसको भी जब मैंने निकाला तो देखा कि उसमें पुचारा देने वाली एक कूची थी जो कि एक-दो रुपये से ज्यादा की नहीं होगी। वह दीवाल पर पुचारा देने वाली कूची थी। उसको देख कर सोचने लगा कि यह विक्षिप्त हो गया है या क्या है। सारा शहर ढह गया है। पुचारा देने के लिए कहीं कोई दीवाल तक नहीं बची है। कोई अभी पुचारा देने की बात सोच भी नहीं रहा होगा और यह बूढ़ा आदमी टूटे-फूटे टिन से अपनी यह कूची निकालने के लिए कब से मलबा हटा रहा है। इससे लगता है कि ऐसी जिजीविषा, जीने की तमन्ना अभी लोगों में है। लेकिन कोई तात्कालिक प्रश्न है, जो पूरे देश को उद्वेलित कर रहा है। वह प्रश्न यह है कि अब पुनर्वासित कैसे किया जाएगा? जितनी आसानी से सत्ता पक्ष के लोग यह दावा कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे इसमें संदेह है। अंजार में ही जहां बहुत तरह की शक्तियाँ राहत के कार्यों में जुटी हुई हैं, वहां लोग बता रहे थे कि अगर दो-तीन महीने के भीतर मलबा नहीं हटा तो कोई भी सरकार हमें पुनर्वासित करने का काम बरसात के पूर्व नहीं कर सकेगी। फिर बरसात में हम पर क्या गुजरेगी इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, वहां सूखा रहता है, लेकिन यदि बरसात ज्यादा हो गई तो क्या होगा? पूरे देश में 15 जून से बरसात का मौसम शुरू होता है, लेकिन गुजरात में लोग बता रहे थे कि कई बार 15-20 रोज पहले ही वहां बारिश शुरू हो जाती है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि जिस गति से काम हो रहा है उस गति से शायद ही तीन महीने के अंदर अंजार का मलबा साफ हो पाए।

इसलिए हम जानना चाहेंगे और देश जानना चाहेगा तथा साथ ही वहां जो जाकर लौटे हैं वे जानना चाहेंगे कि वह मलबा कैसे साफ होगा? उस मलबे की जगह पर जहां जिनके घर थे, बरसात के दिनों में या लू के दिनों में उनके रहने का क्या इंतजाम होगा? क्या अभी तक जो टेंट दे दिए गए हैं वही उस समय काम आयेगे? यह सोचने की जरूरत है और इस बारे में क्या विचार हो रहा है, यह भी देखने की जरूरत है। यह स्वागत योग्य है कि सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं को लेकर कमेटी बनाई है और पहले से जो मैनेजमेंट नेचुरल कैलामिटी को लेकर है उसको सक्रिय किया गया है। हम समझते हैं कि इसका उपाय निकाला जाएगा। एक और नजारा हमने देखा और हम जानना चाहेंगे कि वहां की सरकार इस बारे में क्या कर रही है, वह नजारा यह है कि विभिन्न आर्गनाइजेशन के ट्रकों के जरिए मलबा वहां से उठा कर मैदान में ले जाकर डाला जा रहा है। जिस कंकरीट के साथ छड़ें जुड़ी हुई हैं उन छड़ों के सहित वह मलबा ले जाकर लोग मैदान में डाल रहे हैं। मैंने जब कांडला के नजदीक देखा या मैंने अंजार में देखा या फिर गांधीधाम के निकट देखा और सुदूर कच्छ के किनारे खिरसरा गांव के रास्ते में देखा तो पाया कि जो मलबा ला कर डाला जा रहा है वहां दो-दो हजार की संख्या में हथौड़ा ले कर लोग पड़े हुए हैं और कंकरीट तोड़ कर उसमें से छड़े निकाल रहे हैं तथा टैले पर लाद कर या दूसरे वाहन पर लाद कर उन्हें ले जाया जा रहा है। तब मैंने सोचा कि जरूर इसको खरीदने वाले लोग खड़े हो गए होंगे और इसका बाजार भी खड़ा हो गया होगा, इसीलिए तो इन छड़ों को लूटने के काम में इस तरह से लोग लगे हुए हैं। यह भी एक अमानवीय पक्ष वहां देखने को मिला। हम समझते हैं कि अगर रिलीफ के कार्य की तरफ ध्यान है तो इस तरह के जो कार्य वहां हो रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है और उसके लिए भी अगर कोई तत्काल मॉर्केट खड़ी कर देने वाले लोग हैं तो उसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। महोदय, कई घरों में जाने का मुझे मौका मिला। मैं हलवद की बात बताता हूं। वहां कुछ लोगों ने कहा और इस विपदा की हालत में कोई भी शक कर सकता है कि रिलीफ का जो सामान वहां पहुंच रहा है,

अपराधकर्मी उसे न लूट लेने ऐसा दावा करना गलत होगा और उस सामान का सही इस्तेमाल हो जाएगा, यह भी दावा करना गलत होगा। महोदय, भ्रष्टाचार का यह आलम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। हलबिद में गिरे हुए 60-65 घरों के उजड़े हुए लोग नगरपालिका की जमीन पर एक कोने में अपने टेंट लगाकर बसे हुए हैं और वहां के लोग अनाज नहीं मांग रहे थे। वह यह शिकायत कर रहे थे कि यहां का तालाब एक सौ एकड़ से कम का नहीं है और पहले यहां पानी के इंतजाम के लिए 999 कुएं थे जबकि आज 9 कुएं हैं, उस में 20 फुट तक मिट्टी का सिल्ट हो गया। इस मिट्टी की उड़ाई के लिए एक करोड़ आया, लेकिन उस पर 20 लाख का खर्च भी नहीं हुआ, बाकी सब गायब हो गया। वहां लोगों ने कहा कि उस किनारे पर बी.जे.पी. वाले हैं जहां कि बढ़िया इंतजाम है और हम लोग कांग्रेस वाले हैं, वहां कोई कम्युनिस्ट तो है नहीं। वहां बी.जे.पी. वालों को उत्तरी किनारे पर बसाया जा रहा है और हम लोगों को कहा जा रहा है आप यहां से हटो क्योंकि यह नगरपालिका की जमीन है। महोदय, यह भी एक प्रश्न है कि जो सामग्री या जो मदद वहां भेजी जा रही है, उस का सही-सही इस्तेमाल हो और उस के लिए ठीक-ठीक प्रबंध किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : महोदय, इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि लगभग 1 लाख 63 हजार कच्चे और पक्के मकान गिर गए, उन के बारे में कुछ घरानों ने ऐलान किया कि हम उन को गोद लेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि कितने घरानों ने कितने गांधो या कितने मकानों को गोद लिया। वहां अंजार और गांधीधाम को या जो दूसरे उजड़े हुए कस्बे या शहर हैं, उन को दोबारा कैसे बसाया जाएगा क्योंकि वहां पांच सितारा होटल से लेकर झोपड़ी तक गिर गए हैं, उन्हें कैसे गोद लिया जाएगा और इस मामले में सरकार की क्या नीति है, इस का खुलासा इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि यह किया जाना आवश्यक है।

महोदय, अखबारों में खबर आ रही है कि भुज में 50 हजार टेंटों की कमी है। इस की चर्चा स्टेटमेंट में भी है, लेकिन एक्जैक्टली संख्या नहीं बतायी गयी है। यह कहा गया है कि अमुक-अमुक सोर्स से यह धन आएगा। वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक की बात की गयी है, लेकिन उन से यह असिस्टेंस किस रूप में मिलेगी - मल्टी-लेटरल लोन के रूप में मिलेगी या यूनी-लेटरल लोन के रूप में मिलेगी? किस तरह की यह मदद होगी, यह स्टेटमेंट से स्पष्ट नहीं है। बताया गया है कि 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और गुजरात के लिए इस 21 हजार करोड़ रुपये की भरपाई का इंतजाम विभिन्न साधनों से किया जाना चाहिए। इस में यह नहीं बताया गया है कि किन-किन मदों से यह 21 हजार करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

महोदय, उड़ीसा के अनुभव के आधार पर अंत में यह कहना चाहता हूं कि सांसदों से अपील की गयी थी कि एम.पी. लाड से वे 10 लाख रुपये दें, लेकिन हाउस को यह बताया गया या नहीं बताया गया, मुझे पता नहीं। कोई कहता है 97 दिए, कोई कहता है 37 दिए और सभी सांसदों ने नहीं दिए जबकि इस बारे में एक पत्र भी सांसदों को जारी हुआ था। इस हाउस की तरफ से या एम.पी. लाड की तरफ से इस विपदा पर क्या कंट्रीब्यूशन है? इसलिए मैं यहां कह देना चाहता हूं कि इस बारे में एक नीति अपनाई जानी चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : यह सदन में बताया जाना चाहिए।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : और इस के लिए ज्यादा-से-ज्यादा लोग धन दें, इस के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए और एम.पी. या किसी पार्टी के एम.पी. का समूह गुजरात के किस इलाके में किस कस्बे में या किस मोहल्ले में मिलकर या अकेले-अकेले अस्थाई निर्माण की योजनाओं का चयन कर सकते हैं, इस की इजाजत के लिए नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग 10 लाख दे रहे हैं, वह 20 लाख तक भी दे सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ओझा जी, अब कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मुझे अंतिम बात कह लेने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अंतिम तो आप कई बार कह चुके हैं।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : यह अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सुंदर अंग्रेजी और हिन्दी से वहाँ के लोगों के पेट में कुछ जाने वाला नहीं है और हमारा कर्तव्य सिर्फ भाषण देना नहीं है। एक महीने की सेलरी की बात कही गई, कितने सांसदों ने दिया, कितनों ने नहीं दिया, ये सारी बात यहाँ पर आनी चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : हमने दस लाख भी दिए और सेलरी भी दे दी।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : हम समझते हैं कि जब हाउस में एक स्टेटमेंट मिनिस्टर की तरफ से हो रहा है तो इन सारी बातों पर भी एक स्टेटमेंट होना चाहिए और एक अलग से पैरा इसमें जोड़ा जाना चाहिए, तब हम समझते हैं कि यह स्टेटमेंट पूर्ण होगा। यह भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि यह बहुत अच्छी बात आई है सेलरी की और दस लाख की। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एम.पी.जी. को अगर यह अख्तियार दे दिया जाए कि वे अपनी मर्जी से, अपनी देख-रेख में अपने उस दस लाख रुपए का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से काम भी हो जाएगा और लोग उसमें अपना साहस भी दिखलाएंगे।

मेरी गुजारिश यह है कि एम.पी. से दस नहीं, कह दिया जाए कि वे 25 लाख देंगे, मैं 30 लाख की डिमांड करता हूँ, लेकिन एम.पी.जी. को यह राइट दिया जाए कि वे अपने ढंग से उस काम को करवाएँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं श्री राजू परमार जी को बुलवाऊँ, कि 10 माननीय सदस्य गुजरात के भूकम्प की त्रासदी पर अपने विचार और प्रकट करना चाहते हैं और 4:45 मिनट पर हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे आपकी बातों का जवाब दें। इसलिए कृपा करके जो माननीय सदस्य अब बोलें वे समय का ध्यान रखें।

श्री राजू परमार : उपसभाध्यक्ष जी, 26 जनवरी, 2001 खास तौर से गुजरात के लोगों को हमेशा याद रहेगा कि इस दिन आए भूकम्प ने पूरे गुजरात के लोगों को हिला दिया, खास तौर से कच्छ, भुज, सौराष्ट्र के कई इलाके और अहमदाबाद सिटी में इस भूकम्प की दजह से

*Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने अपनी प्रापटी गंवाई, कई मकानों को नुकसान हुआ और अकेले कच्छ, भुज में हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, अहमदाबाद शहर में करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो प्रापटी का नुकसान हुआ है, वह करीब 21000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। हमारे मित्र और सांसद, श्री ललितभाई मेहता जी जब यहां पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने गुजरात सरकार की काफी पैरवी की, जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी आपके माध्यम से इस हाउस से गुजारिश है कि कम से कम हमारे इस हाउस के सांसदों की एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए। हम वहां पर विजिट करें, सभी पार्टियों के एम.पी. वहां विजिट करें और वहां जाकर देखें कि कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है ताकि पता चले कि गुजरात सरकार ने कितना काम किया है और कितना होना बाकी है। वहां कोआर्डिनेशन का अभाव था, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्पीड से होना चाहिए, उस स्पीड से वह रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी भी मलबे के नीचे लोगों की प्रापटी की सामग्री दबी हुई है। गुजरात सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि यह मलबा उठाया जाएगा या नहीं। जो लोग वहां पर रहते थे, उनको कहां पर बसाया जाएगा, यह अभी तक गुजरात सरकार ने डिक्लेअर नहीं किया है और जब और जगह पर बसाने की बात आएगी तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी भावना को भी ध्यान में रखा जाएगा या नहीं। इस बारे में भी हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, खास तौर से हमारी कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 12, 13 और 14 को कच्छ, भुज इलाके का दौरा किया था और इन तीन दिनों में उन्होंने करीब 18-20 गांवों का भी दौरा किया। उन्होंने वहां पर लोगों से बात की, वहां पर राहत सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उस दौरान जो शिकायतें सामने आईं वे यह थीं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको जो राहत सामग्री मिलनी चाहिए थी, वह उनको नहीं मिल पाई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो एजेंसी कर रही थी, उसमें भी खास तौर पर हमारे सौराष्ट्र में बी.जे.पी. के एम.एल.ए. ज्यादा हैं। इस वजह से वहां वीकर सैक्शन के लोगों को राहत सामग्री मिलने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थीं। महोदय, मेरी आपके माध्यम से गुजरात सरकार से और केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि जब मकान बनाने की बात हो, उनके पुनर्वास की बात हो तो कम से कम इस गलती को न दोहराया जाए, इस बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे गुजरात के चीफ-मिनिस्टर ने पुनर्वास के बारे में जो बात कही है, उन्होंने 7 लाख मकान बनाने की बात कही है। आप जानते हैं कि अब मानसून में केवल तीन, साढ़े तीन महीने का वक्त रह गया है तो इतने कम समय में आप 7 लाख मकान कैसे बनाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। हम जानना चाहेंगे कि इतने कम समय में वे मकान कैसे बनेंगे? मंत्री महोदय इस बारे में भी हमको जानकारी दें और पूरे देश को बताएं कि इतने शॉर्ट पीरियड में वे कैसे इतने मकान बना पाएंगे?

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात में और खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में अभी अकाल की परिस्थिति भी शुरू हो गई है और ज्यादातर वहां पानी की समस्या भी होगी और घास और चारे की प्रॉब्लम भी होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब वहां पानी की तंगी रहेगी तो आप मकान कैसे बनाएंगे? इस बारे में सरकार की क्या राय है, यह भी इस हाउस में हम सबको बताया जाए। महोदय, जो राहत सामग्री वहां पर बांटी गई है, उसके बारे में गुजरात सरकार ने

कहा है कि हमने 3 लाख टेंट की डिमांड की थी लेकिन मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि केवल 64,000 टेंट मिले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, यह मंत्री जी ने नहीं बताया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि जो टेंट मिले हैं, उनमें से कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? हमारी जानकारी के मुताबिक 10 फरसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यानी 30,000 टेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बाकी जो जरूरत है 3 लाख टेंट की, उन टेंटों को आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस बारे में भी हमको बताएं। इन्होंने कहा-कहां इन टेंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इस बारे में स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मंत्री जी ने कहा है कि इतनी राहत सामग्री मिली है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी चाहता हूँ कि जब 1998-99 में कच्छ में साइक्लोन आया था, उस समय 1500 लोग उसमें मारे गए थे और आज भी 1700 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, जिनका पता नहीं है। उसके बाद सूरत में जो आपदा आई, उसमें भी 64 लोग मारे गए और करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कच्छ में 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद 1999 में दोबारा साइक्लोन आया जिसमें डेढ़ सौ लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा कैटल का नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने इन दो-ढाई सालों में केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मांगी और केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता उनको उपलब्ध कराई है, उस सहायता में से कितनी राशि अब तक खर्च हुई है?

महोदय, हमको ऐसा लग रहा है कि गुजरात सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन काम नहीं होता है। जैसे गुजरात सरकार ने साइक्लोन को भुला दिया, हमको ऐसा लग रहा है कि वे बड़ी-बड़ी बातें करके इस अर्थव्यवस्था को भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अहमदाबाद सिटी के लोग हैं, वहां जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो बैंकों में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, जिन्होंने लोन लेकर वे मकान बनाए थे, उनके बारे में सरकार क्या रवैया रखती है? क्या उनको दोबारा से बसाने के लिए सरकार कुछ सोच रही है? क्या सरकार उनको इंट्रस्ट फ्री लोन देने के बारे में सोच रही है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, my party, the AIADMK, expresses its deep condolences to the souls which had departed from us and conveys its solace to the injured ones. Sir, this is a devastating, unprecedented disaster. It has devastated the entire humanity. Every day, there is a report that one part or the other is threatened by earthquakes and tremors. I request that this Government should find out the reasons for these earthquakes and take effective steps to tackle their effects.

Sir, there was a report from the Kutch area. A publication was issued by some of the people--and it was distributed amongst the Members of Parliament also--wherein it was said, Sir, that after the earthquake erupted on the 26th January, for about seven days no steps

were taken in the Kutch area. If steps had been taken immediately, the heavy loss of lives could have been avoided. The estimated loss in that area is about 80,000 people, but in this report it is given that 19,500 people were declared to be dead. There are many persons affected in that area. If rescue operations had been taken immediately, nearly 80,000 people could have been saved. Because rescue operations were not taken up immediately, for seven days there was a heavy loss of life. It is also reported there that the Chief Minister of Gujarat admitted that the administrative machinery had collapsed; no officer was deputed for six long days after the earthquake. Government could not even mobilise teams to assist the foreign team. ...(*Interruptions*)...

श्री संघ प्रिय गौतम : वाईस चेयरमेन सर, कच्छ में जो एक एस0डी0एम0 थे उसका वहां लड़का मर गया, पत्नी मर गई अहमदाबाद में और वह कच्छ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा रहा और अपने लड़के की लाश लेने नहीं गया। ...(*व्यवधान*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : गौतम जी, यह उस अधिकारी के बारे में नहीं कह रहे हैं। ...(*व्यवधान*)...

SHRI R. MARGABANDU: This is the report that has been circulated amongst the Members of Parliament. I am quoting from that. ...(*Interruptions*)...

श्री संघ प्रिय गौतम : वहां कई अफसर मर गए, तहसील गिर गई, कचहरी गिर गई, तथा तहसील के लोग मारे गए और यह कोई उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। ...(*व्यवधान*)... दफ्तर के दफ्तर गिर गए। ...(*व्यवधान*)...

SHRI R. MARGABANDU: You own up your responsibility. You have not taken any steps for one week! ...(*Interruptions*)... You have not taken steps for one week. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मार्गबन्धु जी, आप अपनी बात कहें।

SHRI R. MARGABANDU: The Government of Gujarat was a mute spectator for six long days after the earthquake. This is the report that has been given from that area. I am only quoting from that. I am not accusing the Government.

SHRI LALITBHAI MEHTA: You give us that report. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. MARGABANDU: This is the report that has been given, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Are you going to authenticate that? ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: It is a fact to be verified. Whether it is a fact or not, that has to be verified. ...*(Interruptions)*... It is a fact. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मेहता साहब, आप ऐसा नहीं कहिए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI LALITBHAI MEHTA: He is quoting it from some report. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मेहता साहब, यह शब्द जो आप बोल रहे हैं वह संसदीय नहीं हैं।

SHRI R. MARGABANDU: It is a point for verification. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: He should authenticate it. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: The Government of Gujarat has reported ...*(Interruptions)*... I am reading from the report. ...*(Interruptions)*... I am reading from the report. ...*(Interruptions)*... The Gujarat Government has reported ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मार्गबन्धु जी एक मिनट। आप यह बता दीजिए कि यह रिपोर्ट किसकी है ? ...*(व्यवधान)*... यह किसकी रिपोर्ट है?

SHRI R. MARGABANDU: There is a report presented by the people from that area. ...*(Interruptions)*... It was circulated to all the Governments. ...*(Interruptions)*... The Government of Gujarat has reported ...*(Interruptions)*...

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, where is that report? ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: This is what I came to know. ...*(Interruptions)*... This is a point for verification. ...*(Interruptions)*... If they were to say that immediately ...*(Interruptions)*... I would like to know whether immediate rescue operations had taken place in the Kutch area. ...*(Interruptions)*... I would like to know that. Let them say. ...*(Interruptions)*... Is it not a fact that for six days after the earthquake on

26th January, no rescue operations were undertaken in that area?
...(Interruptions)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr Vice-Chairman, Sir, he knows the rules. ...(Interruptions)...

SHRI R. MARGABANDU: Steps should have been taken immediately. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इसको देख लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन में जो चीज रखी है उसका सत्यापन वह करें या उसको कोट करें या अपने शब्द वापस लें।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इसको कार्यवाही में देख लिया जायेगा और उसको निकाल दिया जायेगा। ...(व्यवधान)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are you authenticating it?
...(Interruptions)...

SHRI R. MARGABANDU: Are they able to substantiate what they have said, that immediately thereafter, they had undertaken rescue operations in the Kutch area? Let them confirm it. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Can you authenticate that report?

SHRI R. MARGABANDU: It is a matter for verification.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अहलुवालिया जी कार्यवाही देख ली जायेगी। अगर वह गलत होगी तो निकाल दी जायेगी। ...(व्यवधान).... मार्गबन्धु जी अब आप समाप्त करिए। ...(व्यवधान)...

SHRI R. MARGABANDU: There is no question of withdrawing. I say, let them confirm.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मैंने आपसे निवेदन किया है, मैंने कहा है कि कार्यवाही देखी जायेगी। अगर उसमें ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, आप यह आदेश क्यों नहीं देते कि अगर वह सत्यापन नहीं कर सकते तो ...(व्यवधान)...

SHRI R. MARGABANDU: There is a newspaper report also.
...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : हां, वह कार्यवाही से निकाल दी जाएगी अगर उसका सत्यापन नहीं होगा। ... (व्यवधान) ... अब मार्गबन्धु साहब समाप्त करिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI R. MARGABANDU: I am reading from the statement that has been made in the House, "the Government of Gujarat has reported that the damage to property and infrastructure is likely to be of the order of Rs 21,262 crores". It is stated that an *ad-hoc* assistance of Rs.500 crores, as announced by the Prime Minister, has been released to the Government of Gujarat. An amount of Rs.500 crores only has been released. From newspaper reports it is understood that thousands and crores of rupees, by way of donation and other things, have been accumulated. I would like to know whether that would compensate the loss of Rs.21,262 crores. There is also a report that there is nobody to receive the donations that are being sent there and that there is no proper coordination in receiving and distributing them. There is such an allegation. I request the Government to constitute block-level committees, at least, for every 10 villages, for monitoring the relief and rehabilitation work. Let proper monitoring work be done. The disaster management plan was not implemented in its letter and spirit. So much of devastation has taken place. The Government says in this statement that steps have been taken. I would like to know, to what extent the distress of the people has been alleviated. Let the Government come forward and make a statement. A mere statement that these things have been done is not sufficient. I would like to know whether the relief has really gone to the people and whether those people have been rehabilitated. Let there be a statement from the Government.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास 36 मिनट बोलने के लिए थे। उसमें से 30 मिनट अहमद भाई बोल चुके और उसके बाद दो मैनबर और कांग्रेस के बोले। वे कितने मिनट बोले, यह आप चेक कर लीजिए। जब हम खड़े हुए तो समय का खयाल करने की बात की जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उसके हिसाब से आपका समय भी बढ़ाया जाएगा। आपके दल के केवल तीन मिनट हैं। आपके दल के समय के हिसाब से हम बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से उनका बढ़ाया है, उस हिसाब से आपका भी बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ाया है, उस हिसाब से आपका बढ़ाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके दल का केवल तीन मिनट है।

श्री संजय निरुपम : मुझे मालूम है, मैं देखकर आया हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो भूकंप की त्रासदी हुई, उसको हम राजनैतिक या साम्प्रदायिक नजरिए से न देखें तो बेहतर होगा क्योंकि जब भूकंप आया और घर गिरे तो पृथ्वी ने यह नहीं देखा कि हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है या सिख कौन है। सारे घर

गिरे, सभी लोग जो वहां पर रहने वाले थे, वे आपत्ति में आए। मैंने जो महसूस किया - मैं खुद भी वहां गया था और मैंने वहां सब देखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पांच हजार कंबल बांटे गये थे जिसमें से अकेले मैं अपनी तरफ से जिस गांव में गया, वह गांव जवाहर नगर है जिस गांव को आपकी सरकार ने अडाप्ट किया, जो पिछले भूकंप में भी बर्बाद हो गया था। उस गांव में मैं खुद कंबल बांटकर आया हूँ। खैर, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। मेरे कहने का आशय है कि गुजरात में जो हादसा हुआ, वह प्राकृतिक था, स्वाभाविक था लेकिन जो विनाश हुआ, वह मानव निर्मित था, ह्यूमैन ऐरर की वजह से ज्यादा विनाश हुआ। उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोष देने से फायदा नहीं होगा। हम आज कहते हैं कि केशू भाई पटेल की सरकार ने नाकारा काम किया, कोऑर्डिनेशन नहीं था, यह नहीं था, वह नहीं था। सारी बातें कहते हैं लेकिन उसकी जगह गुजरात में आज किसी की भी सरकार होती, वह प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकती थी। रिलीफ वर्क और रैसक्यू ऑपरेशन अच्छे ढंग से नहीं कर सकती थी। इसलिए क्योंकि विनाश इतना बड़ा था कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा विनाश हो सकता है। इतना बड़ा भूकंप हिन्दुस्तान में कभी नहीं आया। इसलिए किसी एक सरकार के ऊपर दोष डालने का कोई अर्थ नहीं है। यह सही है कि रैसक्यू ऑपरेशन में हमें जितनी तत्परता के साथ, जितनी क्षमता और जितनी तन्मयता के साथ काम करना चाहिए था, उस तरह की क्षमता हमने नहीं दिखायी, हम नहीं दिखा पाए क्योंकि हम इनकेपेबल थे, हम अक्षम थे, हमारे पास उपकरण नहीं थे, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए जो अत्याधुनिक उपकरण होते हैं और उनके बारे में जानने के लिए जो उपकरण होते हैं, वे सब हमारे पास नहीं थे। दो दिन बाद वे तुर्की से आए, बाकी देशों से, स्विटजरलैंड से आए। कहने का अर्थ है कि कहीं न कहीं हम सब कमजोर हैं। सिर्फ गुजरात सरकार पर दोष डालने का कोई औचित्य नहीं है। निश्चित तौर पर अगर हमारी तरफ से समय रहते अच्छे ढंग से प्रयास होता तो और लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे देशों की जो टीम्स आयीं, जो दल आए, उनको सही ढंग से एंटरटेन नहीं किया गया, उनसे मिलने वाला कोई नहीं था, उनमें से कई लोगों को जाना पड़ा। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी आपत्ति आयी हुई हो, इतनी बड़ी विपदा आयी हुई हो कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो तो ऐसे में इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। इन गलतियों के लिए सीधे किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो मानव निर्मित कारण मुझे महसूस हुए, वह यह कि वहां पर जो इमारतें बनी हैं, वह दोषपूर्ण इमारतें हैं। जो भवन निर्माण के कानून थे, उन कानूनों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया गया। वह सिर्फ गुजरात के भुज में, भुजाऊ में या अहमदाबाद में हुआ, ऐसा नहीं है। मुम्बई में भी हो रहा है। अगर उस रिव्टर स्केल पर मुम्बई में भूकंप आया होता तो वहां पर भी सारी इमारतें गिरती। हमारे पूरे देश में इस समय भवन निर्माण के कानूनों का उल्लंघन भयानक तरीके से हो रहा है। जो बिल्डर्स की लॉबी है, उस लॉबी के साथ हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट में सारे नाम हैं। अगर केशूभाई पटेल का बेटा इनमें इनवॉल्व है, बछुभाई बाला इनवॉल्व है तो साथ-साथ कांग्रेस के लोगों के भी नाम इसमें हैं। सिद्धार्थ पटेल, सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री चिमनभाई पटेल, नरेश रावत, चीफ व्हिप ऑफ कांग्रेस इन लैजीस्लेटिव असेंबली, उसके बाद नरहरि अमीर, फॉर्मर डिप्टी सी.एम.....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप नाम मत लें, आप नाम क्यों ले रहे हैं?

श्री संजय निरुपम : मेरे कहने का अर्थ है कि गुजरात की हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कहीं न कहीं बिल्डर्स को प्रोटेक्शन दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। किसी एक पक्ष के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, हर पक्ष के लोग हैं। यह सिर्फ गुजरात की समस्या है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यह हमारे देश की हर स्टेट की समस्या है, हर शहर की समस्या है। इन बिल्डर्स के खिलाफ सही ढंग से कार्यवाही होनी चाहिए। मंत्री महोदय का जो बयान आया है, उसमें इस संदर्भ में एक भी टिप्पणी नहीं की गयी है। जो कांग्रेस की तरफ से महत्वपूर्ण भाषण हुए। दो महत्वपूर्ण भाषण मैंने ध्यान से सुने। एक अहमद पटेल जी का और दूसरा दवे जी का। दोनों में किसी ने भी बिल्डर्स की समस्या के बारे में नहीं कहा।

श्री अहमद पटेल : मैंने कहा है। मैंने मेशन किया है। मैंने सख्त कार्यवाही की डिमांड की है।

श्री संजय निरुपम : हो सकता है कि मैं सुन नहीं पाया होऊँ। कहने का अर्थ है कि अहमदाबाद में जो इमारतें गिरी हैं, वे पिछले चार-पांच वर्षों में बनी थीं। वहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग नहीं गिरी, वह उसी क्षेत्र में थी। गुजरात कॉलेज की बिल्डिंग नहीं गिरी, यह सब पुरानी इमारतें थीं। कानूनी ढंग से अर्थव्यवस्था प्रूफ बिल्डिंग्स बनायी गयी थीं। जो क्षेत्र सिसमिक जोन-5 में आते हैं और जो भूकम्प के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर भवन निर्माण के कानूनों का उल्लंघन करके भवन बनाए जा रहे हैं। जब मैं भुज गया और वहाँ के लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, हम पिछले पांच-छः सालों से इनकी शिकायतें कर रहे हैं या म्यूनिसिपैल्टी को पत्र लिख रहे हैं कि इन अवैध बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्यवाही करिए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा भी आए तो इससे बहुत ज्यादा विनाश का पैमाना न बढ़े। इसको टालने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं बिल्डिंगों से अर्थव्यवस्था प्रूफ बनाने के बारे में खयाल रखा जाए। अभी हमने मंत्री जी का बयान देखा। उसमें वर्ल्ड बैंक की ओर से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से डालर को कन्वर्ट करने की कोशिश की है और लगभग वहाँ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की सहायता आई है। हर जगह से सहायता आई है। हमारी गवर्नमेंट ने सहायता दी है। हर पब्लिक सेक्टर, यूनिट्स, हर प्राइवेट सेक्टर, हर न्यूज पेपर ने रिलीफ फंड तैयार किया है। बैंकों और अस्पतालों ने यह रिलीफ फंड तैयार किया है। बहुत बड़े पैमाने पर रुपया आया है इसलिए इसका सही उपयोग होना चाहिए। ... (समय की घंटी) ... महोदय, कल मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कारगिल के नाम पर जो फंड तैयार किया था आज तक उस पैसे का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि गुजरात में कारगिल के नाम से जो फंड था उसमें 24 करोड़ रुपया जमा था। उसमें से बीस करोड़ रुपया कहा गया, कुछ पता नहीं है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि भूकम्प के नाम पर, भूकम्प पीड़ितों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह सही व्यक्ति, पीड़ित वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आपने भचाऊ तालुका के बारे में कहा है। मैं भचाऊ गया था और मैंने देखा कि पूरे का पूरा शहर ही तहस-नहस हो गया। अभी भचाऊ तालुका स्टेट गवर्नमेंट ने जब एडोप्ट किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि पूरा तालुका नहीं एडोप्ट किया गया है, पूरे तालुका को गोद नहीं लिया गया है बल्कि भचाऊ के आस-पास के दो-तीन गांवों को गोद लिया गया है। इस शहर को तो कोई हाथ ही

नहीं लगा रहा है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 225 गांवों का पुनर्वसन किया जाएगा। इसके लिए लगभग 600 करोड़ का फंड एनाउंस किया है। इन 225 गांवों में न तो भुज है, न अंजार है, न भचाऊ है और न ही मोरबी है। इन चार क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है, सबसे भयंकर प्रलय हुई है।

श्री ललितभाई मेहता : इन शहरों के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मेहता जी, मंत्री जी यह सब बताने में सक्षम हैं। आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें और इन्हें बोलने दीजिए।

श्री संजय निरुपम : मेरे दिमाग में जो प्रश्न था, वह प्रश्न मैंने यहां रखा है कि निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में साफ ढंग से कुछ करे। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हम अक्षम हैं। इतना बड़ा हादसा था और उससे निपटना भी मुश्किल था। डेथ फिगर्स दिए जा रहे हैं उन्नीस हजार। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे तो लगता है कि बीस-पच्चीस हजार तो अकेले भुज में मारे गए हैं। जानबूझकर मृतकों के आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब घरों के नाम आप बता सकते हैं कि कितने घर कहां-कहां गिरे हैं,

"As per reports received from the State Government, more than 19,000 people have been declared dead and about 1.67 lakh have been injured. About 1.59 crore population in 7,904 villages in 182 Talukas spread over 21 districts have been affected by the earthquake. 1.65 lakh pucca houses, 1.63 lakh kuchcha houses and about 16,000 huts have been fully destroyed, and 4.60 lakh pucca houses, 3.15 lakh kuchcha houses and about 32,000 huts have been damaged."

मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब लाखों की संख्या में घर बर्बाद हुए तो सिर्फ उन्नीस हजार लोग मारे गए होंगे, ऐसा नहीं है बल्कि पूरी ईमानदारी से फिगर्स सामने रखी जा सकती है। सबको मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है। 38 देशों के लोग वहां पर आए हैं। उन्होंने अपने-अपने स्तर पर किया, सब लोग गए, हमने किसी पर मेहरबानी नहीं की। गुजरात में जो आपदा और तकलीफ आई, उसमें हम सब शामिल हुए और जैसा अहमद साहब ने और दवे साहब ने बहुत ही भावुक होकर बताया कि भाई हमारे ऊपर जो विपत्ती आई है, इसमें हमारा साथ दीजिए। हम लोग पूरे देश के लोग, हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर पार्टी, बगैर किसी जाति, बगैर किसी धर्म, बगैर किसी सम्प्रदाय का विचार किए हुए गुजरात के संकट में शामिल हुए। मैं गुजरात को पूरी शुभकामना देता हूँ। वहां कच्छ, भुज और भचाऊ सबका पुनर्निर्माण हो, सारे लोग आबाद हों। यह मेरी कामना और शुभकामना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए गुजरात में भूकम्प के हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री आर.एस. गवई (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य है कि जो गुजरात में मरे हैं, दिवंगत हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दूँ। उपसभाध्यक्ष जी, पहले जो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है वह यह है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ से राहत सामग्री गुजरात के लिए रवाना की और राज्य सभा का सर्कुलर प्राप्त होने से पहले ही मैंने कलैक्टर को लिखा है कि इसके बारे में जो सूचना है वह बदलने वाली है। सूचना या निर्देश तो आदमी के लिए होते हैं कि दस लाख रुपये का रिलीफ गुजरात को भेजो। नौ दिन बाद मैं स्वयं गुजरात पहुँचा। करीब-करीब गुजरात के आठ जिलों में यह भूकंप है और भूकंप से अफेक्टेड विलेजज हैं जिनमें से अहमदाबाद, कच्छ, भुज, सुरेंद्र नगर, बनासकाटा, राजकोट और पाटन जिलों में से करीब-करीब 50-60 गांवों का जायजा लिया है और मैंने चार दिन बारह-बारह घंटे दौरा किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरा भाषण राजकीय भाषण नहीं होगा, टीका-टिप्पणी का भाषण नहीं होगा, मैं जाति और संप्रदायवाद से भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा मगर मैंने जो कुछ देखा है, जो वस्तुस्थिति है, जो वास्तविकता है वह सदन के सामने लाने के लिए विनम्र शब्दों में गुजारिश करूँगा कि इस पर आगे अमल हो। मुझे दुख है कि भूकंप की व्याप्ति बहुत बड़ी थी फिर भी जिस तेजी से, जिस रफ्तार से गुजरात प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था वैसा ध्यान देने में बहुत देरी हुई है। मैं जिस इलाके में घूमा वहाँ मैंने उस इलाके के सारे स्वयंसेवी संगठनों, पूरे राज्य दलों के सामान्य नेताओं और सरकारी पदाधिकारियों से बातचीत की। परंतु आठ दिन के बाद भी न तो पंचायत अधिकारी, न ही रेवेन्यू के अधिकारी हमें सर्वे का डाटा दे पाए। जो मालूमात और सर्वे जमा किया वह सारे मैंने सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवक संगठनों और स्वयंसेवकों से लिए, उससे मेरा खयाल है कि अगर राहत कार्य में तत्परता दिखाई जाती तो - मेरा किसी को दोष देने का उद्देश्य नहीं है - जितने आदमी मरे हैं उनमें से कम से कम हजारों आदमियों को हम जीवित रख सकते थे, यदि रखने की कोशिश करते तो। ठीक है भूकंप का स्वरूप भयानक था फिर भी हमारी तत्परता तो होनी चाहिए थी और इस तत्परता से जो दस हजार लोग जीवित रह सकते थे तो हम इन दस हजार लोगों को जीवन प्रदान कर सकते थे। मैं अखबार की रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ और माननीय मंत्री जी का निवेदन भी मैंने पढ़ा है। मगर जो संख्या डेथ की है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितनी फिगर्स हैं, रिपोर्टेड फिगर्स हैं, गवर्नमेंट मशीनरी होगी या जो प्रेस कहता है वह अपनी जगह होगी, लेकिन जो लोग मिले नहीं हैं उनका संख्या अन-एकॉउन्टेड है। बछाऊ में कितने निकाले, कितने डिटेक्ट हुए और कितने नहीं हुए यह कौन बताएगा? अंजार में कितने मरे होंगे कोई बता नहीं सकता। इतनी भयानक आपदा थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि ऐसे प्रसंग में वहाँ पर चाहे किसी भी राजनैतिक दल का शासन हो, तत्परता की आवश्यकता है। ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा यह भाषण राजनैतिक नहीं है। मैं रापड़ पहुँचा। वहाँ सब लोग आपस में तकरार कर रहे थे कि राहत कार्य के सर्वे में डिसक्रिमिनेशन हुआ है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। अंजार में भी यह बात सुनने में आई। हो सकता है कि संगठन का दोष न हो, आइसोलेटेड हो सकता है। मगर इस संकट की स्थिति में भी मानवता के पुजारी, मानवता के रास्ते पर चलकर स्वयंसेवी संगठनों ने काम किया। मृत्यु बैर को भूल जाती है। ऐसे समय अगर कुछ लोग उस बैर को याद करते हैं तो उचित नहीं है इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, राहत कार्य का मार्गदर्शन करना, राहत कार्य पहुंचाना, इतना सब कुछ आ रहा है उसके लिए डाइरेक्शन बतलाना यह आसान काम नहीं है। सड़कों पर ढेर लगा है और राहत कार्य का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो किसी गांव में टीम जाकर उसको बांटे इसका गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। मैंने वहां पर देखा कि इमारत की तीन मंजिल जमीन के अंदर और तीन मंजिलें ऊपर हैं। अहमदाबाद में मैंने स्वयं यह देखा। मैंने मुंबई में विधायक सोसाइटी बनाई है। वहां 250 फ्लैट बनाए हैं जहां विधायक और एम.पी. रहते हैं जिसका जिक्र अभी यहां हुआ है। ...**(समय की घंटी)**... वहां इतनी बिल्डिंगें गिर गई इसका कारण यह था कि उन पर सीमेंट, लोहा खराब क्वालिटी का था। वहां पर बिल्डिंगें गिर गई और इतने लोग मर गए दोज दर सपोज़्ड टु बी मैन मेड।

जो सर्वे महाराष्ट्र का सेंटर ने किया है, उसके अनुसार नीड बेस्ड प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर उस इलाके में पूरी नीड बेस्ड प्लानिंग

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): 5 बजने वाले हैं। अगर सदन की राय हो और मंत्री जी का जवाब अभी सुनना चाहते हों तो सदन का समय बढ़ा लें।

एक माननीय सदस्य : कल।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इनका जवाब तो हो जाए। ...**(व्यवधान)**... आज ही उत्तर हो जाए।

श्री सुरेश ए. केसवानी (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उत्तर हो जाए। हां हां, आपको भी बोलने देंगे। दो मिनट आप भी बोल लीजिये। लेकिन आपने अपना नाम अभी मेजा है लोगों के भाषण सुनने के बाद। तमाम भाषण हो गये हैं। ठीक है, 15-20 मिनट के लिए सदन को बढ़ा दिया जाए, क्या राय है?

श्री संघ प्रिय गौतम : लोग सुबह से तपस्या कर रहे हैं उनका क्या होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मंत्री जी तो केवल 10 मिनट में अपनी बात कहेंगे। मंत्री जी, आपको 10 मिनट लगेंगे न? मंत्री जी को 10 मिनट का समय लगेगा। दो माननीय सदस्यों के नाम अभी बाकी हैं और केसवानी साहब का नाम अभी आया है। उनको भी समय दिया जाएगा। तीन-तीन, चार-चार मिनट में आप अपनी बात कह लेंगे तो हो जाएगा। मनोज भट्टाचार्य जी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, 5.25 तक हम लोग बैठते हैं। ...**(व्यवधान)**... अहलुवालिया साहब भी बोलेंगे क्या? ...**(व्यवधान)**...

श्री आर.एस. गवई : मेरा सुझाव यह है। मैं तो सम अप कर रहा हूं। मैं कोई ज्यादा समय लेने वाला नहीं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री आर.एस. गवई : मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जो हुआ Thus far and no further. Forget the past. आपको सर्वे करना हो तो वह सर्वे ऐसा हो जिसमें किसी भी तरह का डिसक्रिमिनेशन न

हो। The survey should not be based on any discrimination. This is my suggestion. नम्बर दो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बचाऊ में जो सेंटर बनाया है वहां नीडबेस्ड प्लानिंग पूरे ताल्लुका लेवल पर किया है। वैसे अगर सरकार अडाप्ट कर ले खाली सात गांव मगर वहां क्या-क्या आवश्यकता है, ऐसे 270 गांव हैं, भुज सहसील में कितने टेंट चाहियें, कितने यूटेंसिल चाहियें। The survey should be treated as an ideal one and it should be adopted throughout the affected areas. तीसरा सुझाव यह है कि जो रिलीफ का सामान जा रहा है वह आवश्यक रिलीफ का सामान जाना चाहिये। जैसे कि सुझाव आया कि चीनी नहीं थी। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद संबंधित लोगों से चीनी की मांग की गई और 10-10 किलो के थैले भेज दिये ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में सुविधा हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना है, it should be based on planning and it should not be at random. अगर यह हो सकता है तो इस तरह से राहत हम लोगों को दे सकते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करता मगर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पेटर्न बनाया है ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया समाप्त कीजिये।

श्री आर.एस. गवई : एक सेकेंड। I think despite all political attachments, it is an ideal one. गांव का लोकेशन, डिस्टेंस, पेटर्न क्या है। There should be a need-based survey and needbased planning for the total rehabilitation in the earthquake affected areas. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I am little confused at this hour. Mr. Gautam is saying that I have only two minutes. I am sorry; I can't finish in that period because I have so many points. Sir, I seek your indulgence.

Sir, I try to concentrate on the statement laid on the Table by our hon. Shri Nitish Kumarji. But before that, I feel it necessary to mention certain things. Sir, many of us are anguished over the incident. I must pay my homage to the thousands of people who have died because of this natural catastrophe. I also offer my condolences to the bereaved families and sympathy to the people who have suffered so badly because of this natural calamity. Sir, when you are talking of natural calamity, I feel it pertinent that we must also look into factors like whether there was a warning about the natural calamity or not. I find from the records which had appeared in different newspapers and on different TV channels that well there was not exact warning but there were forewarnings. I quote from *The Times of India*, dated 14.2.2000 where a very interesting report appeared. I am not going through the entire report because it is a very big report. I am only mentioning, "after Jabalpur quake on 22nd May, 1997, the former ISRO Chairman, Satish Dhawan along with seismic experts

V.K. Gour, K.S. Valdia and R.N. Narshima wrote to the Prime Minister demanding the state-of-the-art seismic risk qualification for some of the critical sites could on a priority basis be completed over a shorter period of one to two years." That assessment could never be done. This pertained to the construction of Sardar Sarovar Project which was in the seismic zone four and five. But, Sir, no importance was given to these experts. ...*(Interruptions)*... Please let me finish. Please do not interrupt me because there is not much time at my disposal. Shri J.S. Negi of the National Geophysical Research Laboratory had stated that the Narmada Valley had become a vulnerable rift zone. Arun Singh, a seismic expert in the five-member Review Group of SSP appointed by the Centre had warned in 1995 that the Narmada Valley is reactivating and that this reactivation is taking place is evident from the uniform distribution of epicentres of earthquakes. Besides the risks of the dam, there was a petition in the Supreme Court that had drawn the attention to the risk due to the dam. Reservoir induced seismicity, what is called in short, RIS, is a phenomenon increasingly under scrutiny. Scientist Matin Ahmed had analysed the RIS hazard as early as in 1971. However, the Narmada Control Authority in a booklet issued in March 1993, claimed that the design of the dam is considered to be adequately covering the risks, if any, due to RIS. This petition could not be heard in the Supreme Court. This is number one. Secondly, the Earth Sciences Institute, Thiruvananthapuram, has claimed to have warned the Government of India by the end of December. They sent a report to the Science and Technology Department of the Government of India. Looking at the inflation of the soil, they forewarned that there may be an earthquake or this sort of a calamity in zone four or five. They also warned about some of the zones. This report was quoted in the media, particularly on TV channels, STAR TV, I would mention, presumably on 10th or 11th February. What is being reported is that those reports only gathered dust in the Department of Science and Technology. There was none to look at those reports and take the precautionary measures. I do not blame this Government because I am conscious that the national Governments, not this Government alone, have been indifferent to scientific reports in different times in the past. This is continuing even for the present. Whether some corrective action can be taken in regard to this indifference or not, that is to be considered. This is about the forewarnings about this Gujarat earthquake which has been very, very unfortunate. ...*(Time-bell)*... Yes, Sir. ...*(Interruptions)*... In fact, I do not have a language to express that. What are the measures that we are going to take, to take care of this

sort of calamity in the days to come? When the calamity struck why I was wondering the State Government of Gujarat was virtually in hibernation. For three or four days, it was in hibernation. The hon. Chief Minister of Gujarat, Shri Keshubhai Patelji, either because he got very much panicky or he could not control his emotions, started frightening the people of Gujarat instead of giving them courage, by announcing that there would be another earthquake within the next 48 hours. Perhaps, he consulted some astrologists, which is not at all a science. But some people, unfortunately, in this country, consider astrology also as a science. And he was emotionally drawn by those astrological predictions that there would be another earthquake within the next 48 hours.

Now, I will come to the statement made by Shri Nitish Kumar, the hon. Minister of Agriculture. He has not mentioned, in his statement, about the lakhs of labourers who have migrated to Gujarat for their livelihood. I am told there were about 3-4 lakhs of poor and landless labourers from Jhabua District of Madhya Pradesh, from Rajasthan, from Bihar, who went to Gujarat to earn their livelihood. Many of those labourers were killed. There is no account because the Government considers them as redundant population of this country. No relief has so far been reached to them because they are the poorest of the poor of this country. Many hon. Members talked about caste bias, religious bias, etc. I am not going into all these things because time at my disposal is short. But there is no mention about these people in the statement made by the hon. Minister. Almost three lakhs of people -- I have seen it on Television -- who require hardly Rs. 600 a month for their livelihood are in distress. They have lost everything. Somebody has lost his wife, somebody his son and somebody his daughter. They do not have money. They want to come back to Orissa. They want to come back to Bihar. They want to come back to Rajasthan. They want to go back to Jhabua District, but they do not have a single penny to go back to their own places, to relieve themselves from the agony of the earthquake. There is no mention in the statement about the poorest of the poor, whom, perhaps, the hon. Agricultural Minister also considers as redundant population, and for whom the Government does not care at all. I draw the attention of the hon. Minister to the condition of those people who come from his own State -- Bihar - also.

Sir, there was a complete lack of co-ordination, insofar as the relief work is concerned. It really hurts me when the hon. Prime Minister

also expressed his exasperation. When the entire situation is in a quandary, the hon. Prime Minister, time and again, talked about the lack of co-ordination. But, in the statement, there is no mention about the lack of co-ordination between the officials and the agencies. This statement is far removed from the facts. Regarding the distribution of the relief material, I would like to submit that even after 10 or 12 days, many villages in Bhuj and Kutch could get nothing. What do the poor people do if they do not get any relief? I do not say that this Government is caste-biased. I do not say that this Government is religious-biased.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप समाप्त करें, भट्टाचार्य जी।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I just quote what has appeared in today's newspapers. I will just quote that report. It shows how discriminatory the Government is. I will just quote it and finish my speech. There are many points which I have to cut short because of paucity of time. I am sorry. Because everytime I get an opportunity to speak only at the end. As a result, I am not able to do justice to the issue. Today, in almost all leading newspapers, a newsitem appeared. I have gone through some of the English newspapers -- The Statesmen, The Times of India, etc. I am quoting the report in verbatim. It says, "The Gujarat Government, on Sunday..." - That is yesterday - "...announced Rs. 1,000 crores package aimed at rehabilitating over 3,276 industrial units devastated by the quake..." - According to information that I could gather from different newspapers, the major industries were, fortunately for us, not devastated because of this earthquake since the industries were situated at a safer places - "...The Industry Minister, Shri Suresh Mehta, Gujarat, said units falling in seismic zones 4 and 5 would be entitled to assistance of 60 per cent of the cost towards building repairs, and investment in plant and machinery, with a ceiling of Rs. 60 lakhs..." -- That is Rs. .6 crores would be given as assistance -- "...In addition, the Government would provide bankable loan assistance of Rs. 20 lakhs. No interest would be charged on this amount for two years. The Government would levy electricity charges only on actual consumption of power. Industries affected by the quake would be exempted from payment of minimum charges for a year." Where is the discrimination? The discrimination is here. The thousands of cottage-industries and small-scale industries in Bhuj and Kutch -I know it for certain have been discriminated. Only Rs. 15 crores have been given to those cottage industries...whereas thousands of cottage industries are there, lakhs of artisans are there. Only Rs. 15 crores have been provided

for the rehabilitation of cottage industries, which has suffered huge losses in Kutch, in Saurashtra and in North Gujarat. Here is the discrimination. Here is the class bias. I would say that the Government is fully class biased. The richer things are going to the rich people...*(time-bell)*... I am just finishing, Sir. In Kutch alone, the cottage industries have suffered a loss of Rs. 69.45 crores, whereas the total relief which has been given to the cottage industries is only Rs. 15 crores. The artisans engaged in hand weaving will be paid only Rs.10,000. The Centre has announced a compensation of Rs. 2,500-5000. The Department of Industry of the State Government has sanctioned only Rs. 5,000 for reconstruction of their working places. Sir, I would once again seek your indulgence to ask the Minister to clarify these points, that is, whether class-bias has taken place in relief distribution and in relieving the people from the real agony that they have suffered. I am not comparing with the...*(interruptios)*... Thank you, very much, Sir.

श्री आर.एन. आर्य (उत्तर प्रदेश) : माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस भीषण विपत्ति पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आप ने मुझे अवसर दिया, इस सहानुभूति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें बहुजन समाज पार्टी का होने के नाते अवसर कम ही मिल पाता है, लेकिन लार्स्ट में आपने जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, भूकम्पों का पिछले 50 साल का जो इतिहास रहा है, उसके अनुसार 1950 में असम में 8.5 रिक्टर स्केल के भूकंप में 1538 लोगों की मृत्यु हुई, 1988 में बिहार में आए भूकम्प में 1000 लोगों की मृत्यु हुई, 1991 में उत्तरकाशी में 6.1 रिक्टर स्केल के भूकम्प में भी 1000 मृत्यु हुई, लादूर में 1993 में 6.0 रिक्टर स्केल के भूकम्प में 10 हजार लोगों की मृत्यु हुई, वर्ष 1997 देश में भूकम्प से 43 लोगों की मृत्यु हुई, 1999 में चमोली में 6.8 रिक्टर स्केल के भूकम्प में 110 लोगो की मृत्यु हुई, लेकिन इस भूकम्प का रिक्टर स्केल पर जो मापन था, उसमें काफी विवाद हुआ। हमारे यहां यह 6.9 घोषित हुआ, चाइना ने इसे 7.4 कहा, अमेरिका ने 7.9 बताया। इससे पता लगता है कि हमारे मॅटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट की सही आंकलन करने की तैयारी नहीं थी। इसी प्रकार से मृतकों की संख्या में भी इतना अंतर था कि किसे सही माना जाए, यह समझ नहीं आया। गुजरात के गृह मंत्री पांड्या जी ने यह संख्या 15-20 हजार के बीच कही, वही 31 जनवरी को रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने यह संख्या एक लाख बताई...*(व्यवधान)*... जबकि एक आंकलन के अनुसार अकेले भुज में ही 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह मानव गणना में इतनी बड़ी भूल होना, मेरी समझ में नहीं आया। आपने जानवरों की मृत्यु की बात की। जानवर 18600 मरे और मानव 16927 मरे, यह वहां की रिपोर्ट में है। आपकी रिपोर्ट में भी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन श्री जॉर्ज फर्नान्डीज की रिपोर्ट में कुछ सहानुभूति लगती है। मुझे लगता है कि जो दबे रह गए, सो रह गए और जो डैड बॉडीज निकलकर आईं, उन्हीं के ऊपर आंकलन किया गया। यहां भी सही आंकलन नहीं किया गया।

महोदय, विश्व के लोगों ने जिस सहानुभूति के साथ हमारे पास आगमन किया। हमने उन्हें दिखाया कि हम अकर्मण्य हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपका सिर्फ पैसा देना, पैसे से सारी सहानुभूति पैदा हो जाए तो सारा विश्व पैसे से ही जीवित हो जाए। यह विपत्तियां पैसे से नहीं, सहानुभूति और सक्रियता से डिपेंड करती हैं। यदि कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की अध्यक्ष ही कहें कि हमें शक है कि माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बहन मायावती ने भी कहा कि अनुसूचित जाति के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है। जिस वक्त आदमी दबा होता है, उस वक्त कोई जाति नहीं होती लेकिन जब निकलकर कटोरा लेकर खड़े होते हैं तो प्रशासन के लोग उस वक्त जाति मानते हैं। हमने देखा है, पहाड़ों में घुसकर के काम किया है। वे उस वक्त उन झोपड़ियों की तरफ नहीं देखते हैं। बड़े-बड़े महलों की संख्या का स्टैंडाइजेशन नहीं हुआ। वह महल बड़े-बड़े लोग बनवा लेंगे सहायता में, दलितों की झोपड़ियां जो दिखाई गई हैं, झोपड़ियां बहुत कम हैं और जब जलाई जाती हैं तो ज्यादा दिखाई जाती हैं। 13000 झोपड़ियां दिखाई गई हैं और तमाम कच्चे और पक्के मकानों का वर्णन किया गया है। मैं जानता हूँ कि सहायता के नाम पर मकानों के लिए स्केअरयार्ड का स्टैंडर्डाइजेशन करके और एमाउंट का स्टैंडर्डआइजेशन करके वहां की सिविल जनता के लिए उसका व्यवहार किया जाए। इस प्रकार से जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए एक प्रकार की आधार संहिता बनाई जानी चाहिए। मैं इस बात को कहते हुए क्योंकि हमारे बीच में बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इस बात को कहा है कि इन घटनाओं के बारे में कोई इस प्रकार का ज्योतिष नहीं बना जो यह बता दे कि ऐसी दुर्घटना किसी देश में घटने वाली है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी ने भी कहा है कि No technology has been developed even in Japan or the USA., जहां 1994 और 1995 में बड़े-बड़े भूचाल आए थे, लेकिन उन लोगों ने भी इस बात को माना है। हम जानते हैं कि मशीनरी डेवलप नहीं हुई है लेकिन ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है, हमारे दिल का और शरीर का सही उपयोग होना चाहिए, दिल का भी सही उपयोग होना चाहिए। यह बात दोबारा क्यों आए इतने बड़े मुल्क में। यह बात सही है कि यहां पर अनुसूचित जाति में और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। जब तक होश नहीं होता है तब तक कोई भेदभाव नहीं होता है, आपतकाले मर्यादा न अस्ति, लेकिन जब आपत्ति चली जाती है तो फिर मर्यादा का पता चलता है कि यह अनुसूचित जाति है, यह नीच जाति है, ऐसा भेदभाव अगर होता है, अगर है तो इसको दूर किया जाए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अहलुवालिया जी। वैसे आपके दल का समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ऐसे तो सारे दलों का समय समाप्त हो चुका है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके दल का समय ज्यादा हो चुका है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ठीक है, मैं समय-सीमा में रहूंगा।

उपसभाध्यक्ष जी, यह सत्य है कि एक विनाशकारी भूकम्प ने भुज और कच्छ के इलाके को अपने चंगुल में लेकर एक विनाश का रूप दे दिया और यह एक महज इत्तेफाक है कि आज से ठीक एक महीना पहले, वह 26 जनवरी का दिन था और आज 26 फरवरी का दिन है, लोगों के घर अभी चालीसवां भी नहीं हुआ होगा, लोगों के घर अभी चहल्लुम भी नहीं पड़ा होगा, ऐसे माहौल में हम यहां पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संदन में यह चर्चा हुई, लोगों ने अपने-अपने विचार रखे।

महोदय, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बात कही जाती है। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे विद्वान साथी ने जो बात कही कि देश में कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो इस चीज की पहले भविष्यवाणी कर सके, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। भविष्यवाणियाँ होती हैं और भविष्यवाणियाँ हुई हैं। महोदय, मेरे पास इसी वर्ष का ऐस्ट्रालिजकल ऐन्युअल मैगज़ीन 'बाबा जी' है। यह हंसने की बात नहीं है, जो बात पहले लिखी गई हो और सत्य हो गई हो, वह हंसने की बात नहीं होती। उन्होंने 14 दिसम्बर को लिखा है। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : एक मिनट, अहलुवालिया जी, हम लोगों को इस बहस के लिए समय थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसे अब हम 5.45 पर समाप्त करेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, उन्होंने लिखा कि -

"India -- The planetary configurations reveal that within about one month from 25th December, 2000 some explosions, fires and violence may be feared. Some calamity like earthquake cannot be ruled out."

यह छपा 14 दिसम्बर, 2000 को। फिर दूसरी बात उन्होंने लिखी कि -

"India -- The planetary configurations reveal that within about one month from 24th January, 2001 nature will cause losses .. a strange tragedy is possible on the 26th January, 2001 around 10.00 A.M. This news will cause much frustration. This will be the time to pray which may reduce the impact, but the tragedy cannot be averted. It shall take place on the 26th January, 2001 around 9.25 A.M."

यह उन्होंने 7 जनवरी, 2001 को लिखा।

श्री राजू परमार : आपने कब पढ़ा?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैंने तभी पढ़ा था।

श्री राजू परमार : बताना चाहिए था ना।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यह इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि प्रकृति ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने कुछ नियम भी बनाए जिनमें कुछ प्राकृतिक नियम हैं और कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। हमने इन दोनों का ही तिरस्कार किया, हमने दोनों को मानने से इंकार किया। प्राकृतिक नियम यह है कि सबसे पहले कॉकरोचों को पता लगता है कि भूकंप आ रहा है, सबसे पहले चींटियों को पता लगता है कि भूकंप आ रहा है, सबसे पहले गाय को पता लगता है कि भूकंप आ रहा है, सबसे पहले कुत्तों को, चिड़ियों को, दरख्तों पर बैठे हुए पक्षी-पंखेरू को पता लगता है कि भूकंप आ रहा है लेकिन हम लोगों ने अपने को उनसे दूर कर दिया है।

महोदय, जहां हमने कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं वहां न दरख्त दिखाई देते हैं, न चिड़ियां दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आज हम प्राकृतिक नियमों से दूर होते जा रहे हैं।

इसका दूसरा आधार है कि या तो सेस्मोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या ऐस्ट्रालॉजर बता सकते हैं कि भूकंप आने वाला है।

श्री राजू परमार : सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बता दीजिए कि क्या लिखा है?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वह भी बता दूंगा। तुम्हारे बारे में भी बताऊं क्या? वह भी बता सकता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप अपनी बात कहें अहलुवालिया जी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, या तो हमें सेस्मालॉजिस्ट बता सकते हैं या फिर ऐस्ट्रालॉजर बता सकते हैं कि भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, बारिश होगी, फ्लड आएगा। ये तो हमें बता देंगे कि ऐसा हो सकता है, उससे हम बच तो नहीं सकते लेकिन हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड हैं, उसके हिसाब से अगर मकान नहीं बने होंगे तो वे ढह जाएंगे। वे तो यह बता देंगे कि ऐसी घटना घट सकती है, घटना घट जाएगी लेकिन उस घटना से बचाव के लिए तैयारियां करने की जरूरत है। हमारे यहां इसी चीज की कमी है और यह कमी कोई रातों-रात पैदा नहीं हो गई, या पिछले 15 दिन, 20 दिन, 40 दिनों में पैदा नहीं हो गई, यह जमाने से चली आई है। जिस तरह से हमने अपनी धरोहर, संस्कृति और सभ्यता को छोड़ा है, उस तरह से हम प्रकृति से प्रकोप से पीड़ित हुए हैं। यह तो बात हुई उस प्राकृतिक प्रकोप की जो हमारे ऊपर हुआ और नियति के नियमों के घेरे में पड़कर हमें यह बरदाश्त करना पड़ा।

महोदय, निस्संदेह गुजरात एक वैभवशाली राज्य है और गुजरात के लोग सारी दुनिया में बसे हुए हैं और वे खुशी से लोगों की मदद करने वाले हैं। इसीलिए आज भरपूर मदद सारी दुनिया से उनके पास पहुंची है। हमारी तो अपने वाहेगुरु से यही अरदास है कि बिछुड़ी हुई आत्माओं को वे शांति दें और उन्हें अपने घरों में स्थान दें और जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और गुजरात पुनः स्वस्थ होकर फिर देने की हालत में आ सके। हमारी तो यही गुजारिश है। महोदय, किन्तु सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मंत्री महोदय ने बड़े साफ शब्दों में दो लाईन में कह दिया कि -

"RBI relaxed overdraft norms, advised banks for conversion and re-scheduling of loan and to provide additional need-based loan."

महोदय, इनको चाहिए कि 6 परसेंट के रेट पर वहां के लोगों को सस्ते दर के कर्ज दें ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। रि-शेड्यूल्ड तो जो करेंगे सो करेंगे लेकिन फिलहाल सस्ते दर पर आगे के कर्ज दें।

महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हाऊसिंग डवलपमेंट फाइनैस कमीशन ने सैकड़ों करोड़ रुपया वहां पर लोगों को मकान बनाने के लिए दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां मकानों की इश्योरेंस भी नहीं हुई थी। जब मकान बिना इश्योरेंस के हैं तो उनको इश्योरेंस से भी मदद नहीं मिल सकती। इस प्रकार दोनों तरफ उनको नुकसान हुआ है। जितने इश्योरेंस के क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका तुरन्त निबटारा किया जाए ताकि उनको क्लेम मिल सके, इसका बंदोबस्त किया जाए तभी हम उनको आगे अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बढ़ा सकेंगे। वैसे आज जो वहां रिलीफ बांटने गए हैं या जो हमदर्दी जताने जा रहे हैं वह ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, यह मेला ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उनको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी

होगी। गुजरात सर्वदा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, वह अब पुनः खड़ा हो जाएगा लेकिन सरकार को जो मदद देने की जरूरत है वह तुरन्त मुहैया कराई जाए और आए दिनों में विज्ञान को और प्रकृति की इस संस्कृति और सभ्यता को इग्नोर करने की कोशिश न की जाए और उसके कहने के अंदर ही हम चले तो शायद हम खुशहाल रह सकेंगे। धन्यवाद।

SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, a great deal has been spoken on the issue of the calamity, its ramifications, the ineptitude and incompetence of the local Government to grasp the seriousness of the situation and to devise measures to meet this calamity. So, I am not going to go into those aspects. I think it is the unanimous opinion of this House that it is a total failure of the Government, that the Government has proved beyond reasonable doubt that it is incapable of either to administer or to govern in a situation in which the Kutch region finds itself today.

Sir, I want to go back to the days when this entire area came into being economically. Everyone is talking about Bachau, Bhuj and a number of other areas where the calamity has taken place. My greatest sympathy is with those people who have suffered here. But I want to point out some other issue which is very germane and very relevant and which must be taken into account. Gandhidham and Adipur are the commercial hubs of the entire region. Kandla Port is the main feeding point. This area has suffered continuous calamities. There was a calamity which destroyed the entire Kandla because of a huge hailstorm which came. We talked about so many relief measures. But when we realised what really happened on the ground, there was precious little done and the entire economy suffered seriously. Two years ago, this is what had happened in that region. And that area, already destroyed by that sea storm, was further put to serious sufferings because of the drought situation which was prevailing there during last year, about which also we have done precious little. Now, we have this earthquake because of which the entire commercial hub stands totally destroyed. Kandla port is being killed in a systematic way because the local Government has brought up two other ports in that area with the support of some private sector, and this port is being systematically destroyed. Till today, we do not have a railway system which connects Kandla with Delhi and opens up this entire hinterland for the development of that area. I would like to go back to the days when this land was donated by Maharao of Kutch to the great leader of Sindhis in those days known as Bhai Pratap. 16,000 acres of land was given for development and the Sindhu Resettlement Corporation was set up which was responsible for bringing up Gandhidham, Adipur, and eventually, the Kandla

port. But the Government took away the land from the Sindhu Resettlement Corporation and developed Kandla Port Trust and handed over that land to them. That is not the issue at this point in time. The issue at this point in time is that when the entire economy stands destroyed, there is no one to offer help to rehabilitate these people. A large number of industries have been facing closure because of total neglect of that region over the last two years and the sea storms which had come. Thereafter, today, these industrialists have no help coming from anywhere. First of all, if the Government is serious about rehabilitating that area, they have to rehabilitate the economy of that area, they have to create incomes in that area, and the people who are capable of creating incomes, have to be offered incentives, and the first incentive has to be to declare for five years total tax holiday for the industries which are set up there, and which come up there. They need to be rehabilitated. I want to come to the second part. When Bhai Pratap constructed that area, he had realised that this was a seismic-prone area. All the houses constructed during that time were low houses with ground plus one storey. No further multi-storeyed buildings were permitted in that area. He did not want this construction. For the last five or six years, an irresponsible Government that we have in Gujarat, has permitted an enormous number of multi-storeyed structures which are against the rules. As a result, these are the buildings which have collapsed first. The 23 hotels which have come up in Gandhidham in the last five years, all of them have been razed to the ground. Why has this happened? It has happened because the land has been taken away by the Kandla Port Trust and this Trust has been taking Rs. 12 to Rs. 15 crores annually from people for giving this land. They are neither developing their land nor are they allowing the land to be used properly and created an artificial shortage of land, compelling people to go in for high rise buildings which are against the interest of that region. Sir, I have few other points to make. I would like to say that enormous relief material has come to that area. Everybody has said that there was no coordination, there was no management. I would say that the downstream machinery which is employed there is so callous that it defies all description. There has to be something done rapidly. I have visited that area. I have met people who have been shown different GRs. Signatures are being taken from people for different amounts for the same kind of relief. Enormous amount of fraud is going on at the hands of the Government machinery. Please stop this. I have pointed this out to the Collector. The person who is sitting there, a gentleman known as Mukim,

is a glib talker. Before I finish my sentence, he is ready with the answer. He says, "Point noted!" Everytime I say something, he says, "Point noted! Point well taken!"

I do not know what he meant. He was not willing to let me complete the sentence. What kind of people do we have there? He was more interested in foreign journalists who were visiting. He would like to be photographed! There is a Chief Minister's Secretary sitting there. He also wants to be photographed! He wants to show what great deal they are doing! But in reality, what is happening is, they have been misusing the equipment; all the tents which have come up there have disappeared! We need more tents there because that is an area where even today the tremors are coming; people are not safe over there. Wooden tents need to be created. Enormous amount of wood has come, but no work is going on! I think these are the areas, Mr. Minister, you must look after.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): केसवानी जी, अब आप समाप्त करें।

SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, I will make just one or two points more. Sir, there has been dependence on a variety of private companies which have made pious declarations, which have given large interviews to newspapers that they are far more efficient than the Government, that they are going to do this, that and the other! And I am told that these companies are now making offers to the Government and asking for a *quid pro quo*. They are asking for certain facilities which are unconscionable. Is the Government going to respond to this? I want to know whether the Government is going to barter away the wealth which the Government is controlling, to these companies. There are some serious charges. There is something seriously wrong, something which is filthy and dirty, and I would not like to name these things, and I am sure, the Minister understands what I mean, and this is something which should be prevented. This is an area of national emergency and national emergency must not be allowed as a handiwork in the hands of a few who want to draw or derive unconscionable advantages. I would urge the Minister to kindly see things personally; don't depend on Gujarat Government. It is not their fault. They have a manufacturing defect.

They are incapable of doing anything. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री नाना देशमुख। अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, please allow me to put one question.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बाद में बोल दीजिएगा, उन्हें जवाब देने दीजिए।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, सच पूछा जाए तो उसका शब्दों में बयान संभव नहीं है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने ढंग से वहां की परिस्थिति का वर्णन किया है। गुजरात के लिए तो सचमुच यह और भी भीषण हो जाता है क्योंकि लगातार किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से उन्हें गुजरना पड़ा है। साइक्लोन और अभी इन दिनों भी लगातार दूसरे साल सूखे की मार से वह प्रभावित है और उसके पहले अगर जाएं तो सूरत में प्लेग का प्रकोप हुआ था। ऐसी परिस्थिति में जितने बड़े पैमाने पर यह सब कुछ हुआ - जो आरोप गुजरात सरकार पर लगाए गये हैं कि तत्काल जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वह कदम उठाने में गुजरात सरकार नाकामयाब रही। लेकिन जो कुछ भी हम लोगों के पास रिपोर्ट है, उसके हिसाब से यह सही प्रतीत नहीं होता है। सरकारी मशीनरी का अविभाज्य अंग है - सरकारी कर्मचारी और उसका अधिकारी। जब वे स्वयं और उनके परिवार के लोग प्रभावित हों तो स्वाभाविक है कि ऐसे मसलों में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बावजूद इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिनके घरों में लोग मरे हैं। वे सब ड्यूटी पर आए हैं और उन्होंने काम करना शुरू किया है। हमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उनके ऊपर खुद भी विपत्ती आई लेकिन उसको भुलाकर वे राहत के काम में लगे रहे। इसलिए यह कहना कि सरकारी मशीनरी विफल रही है, यह उचित नहीं है और अधिकारियों के प्रति घोर अन्याय होगा जिन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। यहां इसकी सूचना मिली तो तत्काल प्रधान मंत्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर उसमें पहल की। उस दिन नेशनल क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी मिली, कैबिनेट की भी मीटिंग हुई। हमारे गृह मंत्री जी वहां तत्काल पहुंचे और फिर सब स्थिति का आकलन करके वहां डॉक्टरों की टीम और राहत सामग्री भेजी गई। इन सब चीजों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसका एक संक्षिप्त विवरण हमारे मूल वक्तव्य में दिया गया है और सरकार की तरफ से हर कदम उठाए गए हैं। गुजरात में जो तबाही हुई है और कच्छ के लिए यह कहा गया है कि कितने लोग मरे हैं इसको लेकर एक विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। जहां तक गुजरात सरकार से 24 तारीख तक की सूचना मिली है उसके हिसाब से हमारे वक्तव्य में 19 हजार से अधिक की बात कही गई है। लेकिन जो मृत्यु के आंकड़े हैं, वे 24 फरवरी तक के उपलब्ध हैं। इसके हिसाब से 19,710 मौतें हुई हैं और गुजरात की रिपोर्ट के हिसाब से 200 लोग मिसिंग हैं, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। अभी अहमद साहब ने यह कहा कि वहां शुरू में पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होगी और बाद में कम्पनसेशन के लिए जब कोई क्लेम लेने जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके लिए गुजरात सरकार ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। एक्सप्रेसिया रिलीफ पैकेट के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी जा रही है। आप जब भाषण दे रहे थे तो हमने तत्काल अपने अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ आपन कहा उस सूचना को पास-ऑन किया। जो वहां से जानकारी मिली, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि एक्सप्रेसिया रिलीफ पैकेट के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने ऐसी बात कही है, हम फिर से उनको कहेंगे। किसी जगह अगर कोई स्पेसिफिक बात है...

श्री अहमद पटेल : आप आफिशियल एनाउंस करा दीजिए। We have got written representations from the people of Saurashtra area.

श्री नीतीश कुमार : उनका एनाउंसमेंट है और उन्होंने कहा भी है कि इसकी जरूरत नहीं है बल्कि इस बारे में बहस चलते मेरे पास सूचना आई है। लेकिन फिर भी इस मामले में हम अपने मंत्रालय की तरफ से तत्काल वहां की सरकार से बात करके जरूर हल करने की कोशिश करेंगे। जब कई मामलों में पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो उसकी रिपोर्ट वे कहां से लाएंगे, यह बात सही है। आपने टेंट का भी सवाल उठाया है। टेंट का भी वितरण वहां किया गया है। जो कई प्रकार के डिसक्रिमिनेशन की बात कही जा रही है, जहां तक मुझे स्मरण है प्रधान मंत्री जी ने नेशनल कमेटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाई है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उसमें गुजरात के मुख्य मंत्री भी स्वयं शामिल हुए। उन्होंने मीटिंग में कहा कि अगर कहीं से भी डिसक्रिमिनेशन की शिकायत आई और उसको हमारे सामने लाया गया तो हम उसकी पूरा जांच कराएंगे। इसके लिए जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह पॉजिशन गुजरात की है। किसी भी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन चाहे वह सोशल हो, चाहे वह इकोनॉमिक हो या रिलिजीयस हो, किसी भी तरह रिलीफ के आधार पर कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह गुजरात सरकार का कहना है। अगर इस तरह कोई शिकायत हम लोगों के पास आई तो हम लोग जरूर उसकी जांच के लिए उनसे आग्रह करेंगे। ऐसे मसलों में किसी भी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपने कुछ बातें कही हैं जिसका मतलब कैलेमिटी रिलीफ फंड और नेशनल फंड फोर कैलेमिटी रिलीफ से है, जो कि दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में था। अब तो नेशनल कैलेमिटी कंटीन्जेंसी फंड का गठन हो गया है ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। इसके बारे में आपने कहा कि कुछ डाइवर्ट किए जाने की शिकायत आई है। हम इस मामले को देख रहे हैं और सी.ए.जी. की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं और इसमें सख्त हिदायतें दी गई हैं। जो इलेक्थ फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है उसकी हमने सभी राज्यों को हिदायत दी है कि जो कैलेमिटी रिलीफ का पैसा है वह कैलेमिटी रिलीफ मद में ही जाना चाहिए। कौन-कौन से आइटम इसके लिए मान्य हैं, अमान्य हैं उसकी सूची भी जारी की गई है। अब वे उसी पर वह पैसा खर्च कर सकते हैं कि क्या-क्या नॉर्म्स होगा। कुछ चीजें स्टेट स्पेसिफिक होती हैं इसलिए उनसे भी राय ली जाती है। इसके बारे में आदेश दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि ऐसी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब शायद डाइवर्ट किए जाने की बात नहीं आएगी क्योंकि अब सी.आर.एफ. के लिए उन्हें अलग एकाउण्ट खोलना पड़ेगा। अब नेशनल कंटीन्जेंसी फंड से भी जो अतिरिक्त सहायता मिलेगी, जो रेयर सिविलियरिटी की कैलेमिटी होगी और जब हम एन.सी.सी.एफ. से मदद देंगे तो वह भी उनके सी.आर.एफ. के हैड के माध्यम से खर्च होगी। इसलिए अब वे डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे और यह तभी रिलीज होगा जब वे इसके लिए अलग एकाउण्ट खोलेंगे जैसा कि इलेक्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा है ...**(व्यवधान)**... जी हां, इलेक्थ फाइनेंस कमीशन ने जो कहा है सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी है। जहां तक गुजरात को तत्काल मदद दिए जाने का सवाल है इसका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में किया है पांच सौ करोड़ रुपये की एडहोक असिस्टेंस दी है। गुजरात सरकार का जो मैमोरेण्डम प्राप्त हुआ है उसके आधार पर एक सेंट्रल टीम भेजी जा रही है। इसके बाद जो मदद आगे दी जानी है वह मदद दी जाएगी। यह पांच सौ करोड़ रुपये की मदद की जो बात कही है यह नेशनल कैलेमिटी कंटीन्जेंसी फंड के माध्यम से है। एक बात यह

भी आई कि यदि इसे नेशनल कैलेमिटी न कहें तो किसे नेशनल कैलेमिटी कहें। यह एक विवाद का विषय उड़ीसा के सुपर साइक्लोन के बाद से खास तौर से रहा है। सरकार के सामने यह मजबूरी है कि नेशनल कैलेमिटी यानी जिसमें पूरे देश की मदद की जरूरत है उसके बारे में तो हर व्यक्ति समझ सकता है कि यह नेशनल कैलेमिटी है लेकिन कैसी सहायता, किस प्रकार की सहायता और तकनीकी तौर पर नेशनल कैलेमिटी डिफाइन नहीं है। टेंथ फाइनेंस कमीशन ने भी उसे डिफाइन नहीं किया था। इलेक्ट्रिक फाइनेंस कमीशन ने भी नहीं किया है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल कैलेमिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट गठित की है, सभी पार्टी के नेताओं को मिलाकर, उसे भी यह कहा गया है कि इसके लिए वे पैरामीटर्स तय करें कि किस परिस्थिति में, किस कैलेमिटी को नेशनल कैलेमिटी कहे। सवाल चाहे उड़ीसा सुपर साइक्लोन का रहा हो उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रकार की सहायता दी गई। जहां तक गुजरात का सवाल है उसे हम यह मानकर चलते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर की आपदा है क्योंकि यदि गुजरात जैसी आपदा का राष्ट्रीय स्तर पर सामना नहीं किया जाएगा तो किस आपदा का किया जाए? इसे सिर्फ सरकार ने ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने रिस्पोंस किया है। लोगों ने रिस्पोंस दिया है, राज्य की सरकारों ने रिस्पोंस दिया है। जिसके पास जो था वह उसने रिस्पोंड किया है। मेरे अपने अनुभव हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को मैं वहां था। गृहमंत्री जी के साथ एक दिन था। अगले दिन मुझे मुख्य मंत्री जी के साथ रहकर कुछ घंटे रहकर राहत कार्य देखने का अवसर मिला था। हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। कोई मेडीकल टीम लेकर आ रहा है, कोई खाने की चीज लेकर आ रहा है, कोई पीने का पानी लेकर आ रहा है। जिससे जो बन पड़ा उसने यह किया। जरा सा भी सड़क पर रुकने के बाद चारों तरफ से लोग दौड़ते थे। यह बात सही भी है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे कि कई लोगों को शिकायत होती थी कि मैं आया हुआ हूं, दो घंटे से हूं पर मुझे बताया नहीं जा रहा है। हमने वहां के अधिकारियों से पूछा उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास जो भी साधन मौजूद होते हैं, सरकारी या गैर सरकारी उन्हें मिलाकर हर दिन का हम रूट बनाते हैं और उसके हिसाब से लोगों को भेजते हैं। दिक्कत यह थी कि लोग चाहते थे कि उन्हें तुरंत कोई काम मिले। यह उनकी स्वाभाविक इच्छा थी क्योंकि यदि दूर से कोई काम करने जा रहा है और अगर उसे तुरंत न बताया जाए कि क्या करना है तो उसके मन में असंतोष पैदा होता है। यह बात सही है, मैंने स्वयं देखा है लेकिन वह असंतोष उनका स्वाभाविक है और दूसरी तरफ जो सरकारी मशीनरी लगी है उनकी कठिनाइयों को भी हमें देखना है। इतने बड़े पैमाने पर राहत देने के लिए लोग पहुंचे थे। जितने बड़े पैमाने पर मीडिया के लोग वहां पहुंचे उससे वहां काम करने वालों को कई प्रकार की कठिनाइयां आ रही थी। इसलिए इसके लिए सीनियर आफिसरों को डिप्यूट किया गया। सीनियर आफिसरों के माध्यम से उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई। शुरुआत में कुछ समय के लिए कुछ कठिनाइयां जरूर आई थी लेकिन उसको दूर कर दिया गया। कठिनाइयों को दूर करने का काम सब लोगो ने मिलकर किया है। इसके लिए गुजरात की सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। हम तो चाहते हैं सदन सरकार की सारी मशीनरी को - सरकार ने काम किया है लेकिन आर्म्ड फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आर्म्ड फोर्स भी सरकार का ही एक अंग है। एनजीओज ने काम किया है, सब ने मिलकर काम किया है। मिलजुल कर काम करने से ही यह संभव हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार को पूरी उम्मीद है कि गुजरात फिर से नए ढंग से खड़ा होगा, पूरा कच्छ का इलाका नए ढंग से खड़ा होगा और जो भी आवश्यक होगा सरकार उसके लिए व्यवस्था

करेगी। जितने भी रिलेक्सेशन की बात आपने कही है उन पर विचार करेंगे। कच्छ को जो राहत दी गई है, सहूलियतें दी गई हैं वही सौराष्ट्र को देने के बारे में जो सुझाव हैं वह मैं वित्त मंत्री

जी तक पहुंचा दूंगा। जो सुझाव आपने यहां दिए हैं उन सब सुझावों पर गौर करेंगे। आपने जो प्वाइंट उठाए हैं, जो जानकारी उपलब्ध थी, उसके आधार पर उनका उत्तर देने की कोशिश की है लेकिन फिर भी उन बिन्दुओं के बारे में जिनकी जानकारी हमें गुजरात से प्राप्त करनी है, वहां से प्राप्त करके आपको दे देंगे। धन्यवाद।

श्री अहमद पटेल : मैंने दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। जो मेन मुद्दा था वह इमीडिएटली टेंटों को देने के बारे में था और टेम्परेरी सेल्टर के बारे में था। मैं जानना चाहता हूं कि कितने टेंटों की आवश्यकता है और कितने अभी तक उपलब्ध कराए गए हैं? बाकी एनजीओज द्वारा जो एडवाइज का सवाल है, उसमें जो दिक्कतें हैं उनको कब तक हल किया जाएगा?

श्री नीतीश कुमार : जहां तक टेंटों का सवाल है इसके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उन्होंने जो बांटे हैं वह 63 हजार हैं। प्लास्टिक सीटें जो वहां बांटी गई हैं उनकी संख्या 1 लाख 19 हजार है। जो टेम्परेरी सेल्टर की बात का मुख्य मंत्री ने ऐलान किया है उसके बारे में पूछा गया कि यह कैसे संभव है तो इस बारे में उनका यह कहना है एक कमरा हम बरसात होने से पहले मुहैया करा देंगे। इसके लिए गुजरात सरकार ने एक पैकेज रीहैबिलिटेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन फार अर्थक्वेक विक्टिम फार गुजरात इस नाम से बनाया है। गुजरात में यह जो डिजास्टर हुआ है इसके मैनेजमेंट के लिए एक अथारिटी मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। सारा पैसा उसमें जाएगा। उसके माध्यम से सारा काम करेंगे। अगर माननीय सदस्यों की दिलचस्पी होगी तो हम गुजरात सरकार से यह पैकेज मंगवायेंगे। सरकार की तरफ से यह बांटा भी गया है। एम्पावर्ड ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। जो भी इसमें दिक्कतें होंगी यहां पर निर्णय लेकर उनको दूर किया जाएगा और जहां भी रिसोर्स पुल करने हैं वह किए जायेंगे। आपको मालूम ही है एनसीएफ से उनको मदद मिलेगी सर चार्ज जो टैक्स पर लगाया गया है उसके हिसाब से जो पैसा प्राप्त होगा, वहां जितनी जरूरत होगी वह दिया जाएगा।

इसके अलावा इंटरनेशनल अरिस्टेंस में भी इसके लिए नेगोसिएशन चल रहा है। तो इस प्रकार से पूरे इलाके को फिर से बसाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सबों के सहयोग से यह यथाशीघ्र संभव हो पाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ...(व्यवधान)... हो गया। देखिए सारी बातें आ गईं ...(व्यवधान)... सारी बातें आ गईं।

एक माननीय सदस्य : हमारे सवालों का जवाब नहीं आया।

6.00 P.M

STATEMENT BY MINNISTER

Outbreak Of fever in Siliguri, West Bengal

THE MINISTER OF HEALTH and FAMILY WELFARE (DR. C. P. THAKUR): Sir, I would like to brief the House on the recent outbreak of an undiagnosed fever in the district of Siliguri, West Bengal which has caused high mortality and concern amongst the local population.

According to the information received from the State health authorities, patients with symptoms of high fever, vomiting, delirium and coma within a period of three to four days, were first reported on 5th February, 2001. Altogether 9 persons were affected with these symptoms and 6 of them died. On receipt of this information, State Government health officials accompanied by experts from medical colleges of Kolkata and Institute of Tropical Medicine, Kolkata visited Siliguri to investigate the incident. Between February 16th and 21st, 62 persons suffered from low-grade fever, sore throat, respiratory distress and pulmonary oedema.

On receipt of information from the Chief Secretary, Government of West Bengal, the Department of Health sent on 23.2.2001 eleven experts -- three from National Institute of Communicable Diseases, New Delhi; six from NIV, Pune, and two from AIIMS, New Delhi -- to assist the State health authorities in their efforts in diagnosis and treatment of the disease.

The clinical features of the infection are mainly abrupt rise of fever, headache and body ache. Within one or two days, the patients are seen to develop confusion and go into coma. Some of the patients developed myoclonic jerks, or even convulsions. Some also experienced breathing difficulty. There was no indication of jaundice or infection of urinary tract or haemorrhagic fever. Physical examination did not show neck rigidity. Liver function tests were normal. Chest X-ray showed bilateral diffused opacities. Cerebrospinal fluid examination was normal except raised pressure. The infection was observed to have a short incubation period, with neurological abnormalities suggesting of encephalitis syndrome -- but the pathological reports did not support this diagnosis. Further, it was observed that the spread of this infection was marked amongst medical personnel and relatives who came in close proximity of the patients.

As reported up to this morning, 62 persons have been identified to be having this disease and 35 have expired. It has been observed that